● वर्ष-3

● अंक-102

रायपुर, गुरुवार
07 दिसंबर 2023

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› बिस्तर के पास रखकर कभी ...

किसे मिलेगी कमान? प्रधानमंत्री लेंगे फैसला!

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजे आए हुए। 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन भाजपा ने अभी तक इन राज्यों में मुख्यमंत्री पद को लेकर खुलासा नहीं किया है। तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी जीत के बाद मंगलवार को रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी थी। सात दिसंबर को वह शपथ भी ले लेंगे। तीनों राज्यों को लेकर हर तरफ एक ही सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल इन राज्यों में यही है कि क्या भाजपा अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जताएगी या किसी नए पर दांव लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। ऐसे में इन राज्यों में किसी नए चेहरे के मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नेता की मुलाकात हो चुकी है। मुख्यमंत्री को लेकर मैराथन बैठक भी की जा चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इन तीनों ही राज्यों में भाजपा अपनी नई पौध को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। आज देर रात या कल सुबह तक इन राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। पर्यवेक्षक संभवत केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय को विधायकों को बताएंगे और सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जाएगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर अंतिम फैसला मोदी को ही लेना है।

रेस में कौन

राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में वसुंधरा राजे के अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालक नाथ, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी जैसे नाम भी शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव का भी नाम चर्चा में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वहां सीएम शिवराज सिंह चौहान को आगे नहीं किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने राज्य में पार्टी का पिछले 18 वर्षों से नेतृत्व किया है। ऐसे में उन्हें किनारे करना पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद सिंह पटेल भी मुख्यमंत्री पद की रेस है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री का रेस दिलचस्प है। यहां रमन सिंह प्रबल दावेदारों में से जरूर हैं। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, अमर अग्रवाल, रेणुका सिंह, अरुण साव और ओपी चौधरी जैसे नाम की भी चर्चा तेज है।

जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो बिल पास

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज सत्र का तीसरा दिन था। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े दो बिल जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन दोनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब दिया। हालांकि, अमित शाह के संबोधन के दौरान लोकसभा में जबरदस्त तरीके से हंगामा भी देखने को मिला। वहीं, डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने लोकसभा में अपने दिए बयान पर खेत व्यक्त किया और इसे वापस ले लिया। इसे सदन के कार्यवाही से भी हटा दिया गया। राज्यसभा में आज देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई।

लोकसभा की कार्यवाही

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान हुए दो 'बड़े ब्लंडर' (गलतियों) का खामियाजा जम्मू-कश्मीर को

वर्षों तक भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए उनका कहना था कि नेहरू की ये दो गलतियां 1947 में आजादी के कुछ समय बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय संघर्ष विराम करना और जम्मू-कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की थी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के कई नेता कश्मीर की बात आने पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनावश्यक आलोचना करने लगते हैं और इस मुद्दे पर सदन में एक बार पूरे दिन चर्चा करा ली जाए तो 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो जाएगा।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को विपक्षी दलों से देश को उत्तर और दक्षिण भारत के आधार पर नहीं बांटने को कहा। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद की हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ टिप्पणी का समर्थन करते हैं? लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अपने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से संबंधित एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' का विचार लेकर आए हैं, ताकि पूरे देश को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करने की एकल पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से एकजुट किया जा सके। पिछले दिनों पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12 सांसदों में से 10 ने बुधवार को संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों ने बताया कि दो अन्य सांसद भी जल्द इस्तीफा देंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस्तीफा देने वाले 10 सांसदों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद पटेल सहित नौ लोकसभा सांसद और एक राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। द्रमुक सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने अपनी एक विवादित टिप्पणी के लिए बुधवार को लोकसभा में खेद जताया और अपने बयान को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान कहा, ''मेरे द्वारा कल दिए गए बयान से सदस्यों और जनता के किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उस बयान को वापस लेता हूं। मैं आग्रह करता हूं कि उसे कार्यवाही से हटाया जाए। मैं खेद जताता हूं।'' पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने कहा, '' बयान को पहले ही कार्यवाही से हटा दिया गया है और आपने खेद जता दिया है, मामला खत्म हो गया।''

राज्यसभा की कार्यवाही

राज्यसभा में बुधवार को विभिन्न विपक्षी दलों ने देश के आर्थिक विकास के सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े चिंताजनक स्तर पर पहुंच गये हैं और सरकार को जमीनी वास्तविकताओं को समझकर उनका समाधान करना चाहिए। 'देश में आर्थिक स्थिति' विषय पर उच्च सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि आम तौर पर आर्थिक आंकड़े भूलभुलैया होते हैं। भाजपा के महेश जेठमलानी ने कहा कि भारत के विकास के बारे में विश्व बैंक के पूर्वानुमान बुरी तरह से विफल रहे हैं क्योंकि वर्तमान वित्त वर्ष की पिछली दो तिमाहियों में विकास दर काफी अच्छी रही है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों द्वारा देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर किए गए दावों को गलत बताते हुए कहा कि औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

धारा 35ए को असम में खत्म नहीं किया गया तो 15-20 साल बाद राज्य में घुसपैठियों की सरकार बनेगी!

नई दिल्ली। भारत की प्रगति और विकास का सारा श्रेय सिर्फ नेहरू-गांधी परिवार को ही देते रहने वाले कभी यह नहीं बताते कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर में धारा 35ए लगा कर इस प्रदेश को देश से कई मायनों में दूर कर दिया था।

नेहरू की इस गलती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाकर सुधार दिया था जिससे जम्मू-कश्मीर का असल मायनों में भारत के साथ संपूर्ण विलय हो गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने जो गलती की थी उसे कौन और कब सुधारेगा?

हम आपको बता दें कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए असम में धारा 6ए लगा कर खतरनाक काम किया था। एक तरह से धारा 6ए के माध्यम से बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता देने की साजिश रची गयी और आबादी का संतुलन बिगाड़ कर अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे किये गये।

क्या है 6ए?

हम आपको याद दिला दें कि भारत के नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए को असम समझौते के अंतर्गत आने वाले लोगों की नागरिकता के मुद्दे से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। 1985 में संशोधित किये गये नागरिकता अधिनियम के अनुसार जो लोग 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से असम आए हैं और तब से असम के निवासी हैं, उनको भारतीय नागरिकता दी जायेगी। हालांकि इसके लिए उन्हें धारा 18 के तहत खुद को पंजीकृत कराना होगा। इस प्रकार, उन बांग्लादेशी प्रवासियों को आसानी से नागरिकता प्रदान की जा सकती है, जो 25 मार्च 1971 से पहले असम आए थे।

चेन्नई में अब भी बाढ़, लगातार तीसरे दिन कई क्षेत्रों में बिजली नहीं

चेन्नई। चक्रवात मिचौंग के बाद से जूझ रहा है। स्थानीय लोगों को बुधवार को शहर और पड़ोसी इलाकों के कई हिस्सों में जलभराव और बिजली व्यवधान से जूझना पड़ा। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में एहतियाती उपाय के रूप में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई है क्योंकि केबल पानी में डूबे हुए हैं और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रमुख समाचार

भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति का निर्माण होने वाला है पूरा

अयोध्या। पूरा देश और दुनिया अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण का पूरा होने का इंतजार कर रही है। श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने वाला है। मंदिर निर्माण के साथ ही मंदिर में रामलला की तीन मूर्तियों का भी निर्माण किया जा रहा है। राम लला की मूर्ति निर्माण का काम भी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। रामलला की तीन अलग अलग मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है, जो अलग अलग तीन प्रमुख मूर्तिकार कर रहे है। ये जानकारी श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को दी है। उन्होंने बताया कि रामलाल के बालपन स्वरूप की मूर्ति 90 फीसदी तैयार हो गई है। रामलला का विग्रह इसी के साथ पूर्णता की ओर है। इन तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन आगामी 20 दिसंबर तक कर लिया जाएगा। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटा हुआ है।

कर्नल समेत पदाधिकारियों की पदोन्नति नीति में बड़े बदलाव, 2024 में एक जनवरी प्रभावी होंगे नियम

नई दिल्ली। भारतीय सेना एक व्यापक पदोन्नति नीति ला रही है। अगले साल के पहले दिना यानी, एक जनवरी, 2024 से बदलाव लागू हो जाएंगे। नई पदोन्नति नीति में कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के सैन्य अधिकारियों के चयन के लिए पदोन्नति नीति की व्यापक समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सुरक्षाबलों की लगातार बदल रही परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रमोशन की नई नीति तैयार की गई है। सेना की नई नीति में सेना के आंतरिक और बाह्य दोनों पहलुओं का ध्यान रखा गया है। पदोन्नति नीति के बारे में भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान हालात के साथ-साथ उभरती परिचालन चुनौतियों का सामना करने के लिए जैसा नेतृत्व जरूरी है, उन आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझने और उसके अनुसार पदोन्नति के फैसले लेने में मदद मिलेगी। भारतीय सेना के बयान के मुताबिक पदोन्नति के संबंध में बनाई गई नई व्यापक नीति अधिकारियों को पदोन्नति के बढ़े हुए अवसर प्रदान करती है। एक जनवरी, 2024 से नई नीति के लागू होने के बाद भारतीय सेना में मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों को आगे और भी पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।

गठबंधन में बढ़ सकती है दरार! सीएम फेस के लिए संजय ने आगे किया उद्धव का नाम

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने बुधवार को अपनी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे का नाम तब लिया जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या 2024 के आम चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक के पास प्रधान मंत्री पद का चेहरा होना चाहिए। हालाँकि, उन्होंने सीधे तौर पर ठाकरे का नाम दौड़ में डालने से बचते करते हुए कहा कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहते जिससे पार्टियों के बीच दरार पैदा हो। इंडिया को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होगी। वास्तव में एक चेहरा होना चाहिए। उद्धव ठाकरे एक हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी चेहरा हैं। जिस व्यक्ति को इंडिया गठबंधन के सदस्यों की मंजूरी मिलेगी, वह (पीएम) चेहरा हो सकता है। मैं बाहर कुछ भी नहीं कहना चाहता जिससे गठबंधन में कोई दरार पैदा हो। राउत ने आगे कहा कि आज शाम को बैठक होने वाली थी... ममता जी के घर में कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि स्टालिन जी राज्य में बाढ़ की स्थिति को लेकर काम कर रहे हैं।

द्रमुक सांसद की टिप्पणी को लोस की कार्यवाही से हटाया गया

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिंदी भाषी राज्यों को लेकर द्रमुक सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार द्वारा मंगलवार को सदन में दिए गए एक बयान को कार्यवाही से हटा दिया है। सेंथिल कुमार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए हिंदी भाषी राज्यों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''हाल में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों पर टिप्पणी करते हुए मैंने अनुचित तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल किया था। उस शब्द को इस्तेमाल करने की कोई मंशा नहीं थी और मैं इससे गलत संदेश जाने पर माफी मांगता हूं।'' भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि कुमार ने अपने बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है।

230 में से 90 नवनिर्वाचित विधायकों पर आपराधिक मामले, 89 फीसदी करोड़पति

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने और उसके नतीजे घोषित होने के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)

ने अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें यह खुलासा हुआ कि राज्य के 230 में से 90 नवनिर्वाचित विधायक यानी करीब 39 फीसदी विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर एक गैर-लाभकारी संगठन है जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का खुलासा करता है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में विश्लेषण किए गए 230 में से 90 विजेता उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसी तरह, राज्य में 230 में से 34 विजयी उम्मीदवारों यानी लगभग 15 प्रतिशत ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। आपराधिक मामले वाले इन 90 विधायकों में से 51 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के, 38 कांग्रेस पार्टी के और एक भारतीय आदिवासी पार्टी के हैं।

विपक्ष को बदलने होंगे अपने तौर-तरीके

राजेश बादल

5 विधानसभाओं के परिणाम सामने हैं। प्रतिपक्ष की निर्बल काया जीतोड़ मेहनत के बाद एक बार फिर चुनावी मंच पर उपस्थित है। पिछले आम चुनाव में कांग्रेस ही नहीं, समूचे विपक्षी दल अपने कुपोषित चेहरे को लेकर सामने आए थे। जाहिर है कि चार सालों में किसी पार्टी ने कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस तथा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ताकत बढ़ाई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जब आकाश-पाताल एक किया, तब कहीं वे तृणमूल कांग्रेस का किला बचा पाईं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस यह करिश्मा नहीं कर सकी। उसने अपनी गलतियों से आम आदमी पार्टी को उपहार में सत्ता दे दी।

अलबत्ता, वह भाजपा से हिमाचल और कर्नाटक तथा तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति से सरकारें छीनने में कामयाब रही। लेकिन वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने मजबूत किले गंवा बैठी। इन सबका क्या संदेश और संकेत है? स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा तो यही कहती है कि निर्वाचित सरकारों को पोखरों की शक्ल में नहीं, बल्कि बहती हुई नदी के निर्मल पानी की बहती हुई धारा के समान होना चाहिए। इस नजरिए से राजस्थान ने 25 बरस से हर चुनाव में पार्टी को बदल देने की परंपरा बना ली है। जब किसी राज्य या केंद्र सरकार को केवल 5 साल के लिए हुकूमत मिलती है तो उसमें काम करने की जिजीविषा बनी रहती है, भ्रष्टाचार कम होता है और चुनाव जीतने के लिए अनैतिक रास्ते नहीं अपनाए जाते। दूसरी ओर विपक्ष को भरोसा रहता है कि उसे अगली बार सत्ता संभालनी है इसलिए वह अपने कार्यक्रमों और नीतियों की धार निरंतर तेज रखता है। यही एक संवैधानिक लोकतंत्र की परंपरा है।

इस परंपरा में विपक्ष और पक्ष के बीच कोई बहुत अधिक फासला नहीं रहता। दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। अगर यदि पक्ष के पहिए का आकार ट्रैक्टर के आकार के बराबर हो और प्रतिपक्ष के पहिए का आकार किसी स्कूटर के पहिए के बराबर हो, तो फिर जम्हूरियत की गाड़ी का ईश्वर ही मालिक है। पक्ष तो कभी नहीं चाहेगा कि विपक्ष के पहिए का आकार बड़ा होता रहे और सशक्त प्रतिपक्ष उसके लिए मुसीबत खड़ी करता रहे, इसीलिए वह प्रतिपक्ष को दुर्बल बनाए रखने की कोशिशें करता रहता है। तो पक्ष की इन कोशिशों के मुकाबले के लिए आज का विपक्ष कितना तैयार है? वह चुनाव-दर-चुनाव अपना बिखरता हुआ जनाधार कैसे एकत्रित करेगा और क्या उसके लिए हालिया चुनाव कोई गंभीर संदेश, संकेत या चेतावनी देते हैं? यकीनन सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस को गहरा आघात लगा है। नतीजे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आमने-सामने का मुकाबला था और भाजपा, कांग्रेस करीब-करीब 40 फीसदी वोटों के ढेर पर बैठी थीं। इन प्रदेशों में सिर्फ दो-चार प्रतिशत मतों के अंतर पर हार-जीत होती है। ऐसे में कांग्रेस ने इतना छोटा फासला घटाने के प्रयास क्यों नहीं किए? कांग्रेस जानती थी कि थोड़े समय पहले ही इंडिया नाम से गठबंधन का एक ताकतवर चेहरा बना है। इस गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की निगाहें उस पर लगी हैं।

लेकिन, शायद कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व ही अपने आप में गंभीर नहीं था। उसने पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में हार से सबक नहीं सीखा क्योंकि कमोबेश उन राज्यों में हार के जो कारण हैं, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी वही वजहें हैं। उम्मीदवारों के चुनाव में गलतियां और तीनों क्षत्रपों कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता इसका बड़ा कारण है। इसके अलावा भले ही दो-चार फीसदी मत बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रहे हों, कांग्रेस को उनकी उपेक्षा करने का अधिकार नहीं था। खासतौर पर उस स्थिति में जबकि वे दल कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। पर, कांग्रेस के स्थानीय क्षत्रपों ने उनकी अपमान करने की हद तक उपेक्षा की। बदले में उन्होंने कांग्रेस को हार सौंप दी। दरअसल, कांग्रेस में पर्याप्त शोध और मुद्दों के बारे में जमीनी अध्ययन की कमी भी पार्टी की देह में बीमारी की तरह फैल गई है। संगठन की गांव-गांव में काम कर रही इकाइयां अब नजर नहीं आतीं। कांग्रेस सेवा दल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जैसे पार्टी के आनुषंगिक संगठन आज भाजपा के आवरण में छिपे दिखाई देते हैं।

अध्ययन के लिए यह एक दिलचस्प आंकड़ा हो सकता है कि जब 1980 में भाजपा का गठन हुआ, तब उसका मतदाता प्रतिशत 10 से 15 प्रतिशत के बीच था और कांग्रेस का मत प्रतिशत लगभग 40 से 35स फीसदी था। इसके बाद साल-दर-साल चुनाव होते रहे और भाजपा धीरे-धीरे अपना जनाधार बढ़ाती रही। आज उसका मत प्रतिशत 40 फीसदी से ऊपर है। दूसरी तरफ कांग्रेस तैंतालीस साल पहले के जनाधार पर ठहरी हुई है। आज भी उसका मत प्रतिशत 40-42 पर ही ठहरा हुआ है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि जब भाजपा अपना नया जनाधार 1980 से करीब 30 प्रतिशत बढ़ा सकती है तो कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ, जो वह आधी सदी के बाद भी मतों के उसी चार दशक पुराने ढेर पर बैठी हुई है। आत्ममंथन के लिए कांग्रेस को यहां से एक बिंदु मिलता है। यदि, लोकसभा चुनाव में प्रतिपक्ष को अपने पहिए का आकार बड़ा करना है और इंडिया की अगुआई करना है तो उसे अपने मतों का ढेर ऊंचा करना होगा।

चुनाव जीतने के बाद भाजपा विधायक बोले- बिना भेदभाव होगा विकास, क्षेत्र की जनता का जताया आभार

कोरबा। कोरबा में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन ने पत्रकारों से कहा कि चुनाव के बाद क्षेत्र की सभी जनता उनके लिए समान है और विकास कार्य की गाथा बगैर भेदभाव के लिखी जाएगी। सभी ने समर्थन दिया। इस वजह से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इस मौके पर कटघोरा विधायक ने कहा कि कटघोरा को जिला बनाने का प्रयास करते हुए अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में सबसे पहले जिलाध्यक्ष डॉ.राजीव सिंह ने कहा कि भाजपा के दो विधायक चुनाव में जीत दर्ज करने में सफल हुए हैं इसका श्रेय कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों जाता है। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए शहर विधायक लखन लाल देवांगन ने दोहराया कि चुनाव में जीत दर्ज हो चुकी है। अब उनका पूरा ध्यान शहर के विकास के लिए रहेगा। घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए हैं उसका शत प्रतिशत क्रियान्वयन करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। मसलन राखड़, जाम की स्थिति, सड़कों का निर्माण पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र की जनता ने धन बल को परास्त करते हुए जनबल का सहयोग किया।

विधायक लखनलाल देवांगन ने कहा कि कांग्रेसियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम की ओर भी ध्यान नहीं दिया, इस वजह से विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र से उन्हें भरपूर समर्थन मिला जिसके लिए सभी का आभार। मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय हाईकमान द्वारा किया जाएगा। इसके पूर्व में कभी भी मेरे द्वारा किसी भी पद की मांग नहीं की गई। पार्टी ने खुद ही उन्हें महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। इस बार भी कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण पद मिलने की संभावना है।

प्रेसवार्ता में मौजूद कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने भी कटघोरा क्षेत्र की जनता जर्नादन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कटघोरा शहर में काफी मात्रा में जमीन का अधिग्रहण हुआ है। इसे लेकर आगामी दिनों में तोड़-फोड़ का अभियान चलाया जाएगा। इसी तरह क्षेत्र की प्रमुख सड़कों के त्वरित निर्माण के लिए एसईसीएल के अधिकारियों से मुलाकात कर कार्य योजना बनायी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कटघोरा को जिला बनाने की दिशा में पूरजोर प्रयास होगा। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर सहित वरिष्ठ भाजपा नेता जोगेश लांबा, अशोक चावलानी, गोपाल मोदी, हितानंद अग्रवाल, नरेन्द्र देवांगन, प्रफुल्ल तिवारी, आरिफ खान सहित सहित सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांकेर में नक्सलियों की नापाक साजिश नाकाम 5 किलो का कुकर बम फोर्स ने किया बरामद

कांकेर। सुरक्षा जवानों ने एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत को उजागर किया है।सुरक्षा बल ने आमाबेड़ा मेन रोड पर छिपाकर प्लांट किए गए कुकर बम को बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि नक्सलियों ने कुकर बम को चुनाव के पहले लगाया था ताकि मतदान दल और फोर्स को नुकसान पहुंचाया जा सकें। लेकिन क्षेत्र में सघन गश्त के कारण अपने नापाक इरादों पर नक्सली कामयाब नहीं हो पाए। कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि थाना आमाबेड़ा से डीआरजी बल रोड ओपनिंग सर्चिंग के लिए थाना ग्राम गुमझीर मलांजकुडूम की ओर रवाना हुआ था। गश्त के दौरान कांकेर आमाबेड़ा मुख्यमार्ग पर गुमझीर और पूसाघाटी के बीच दल को एक कुकर बम मिला। कुकर बम में 5 किलोग्राम विस्फोटक था। डीआरजी आमाबेड़ा और बीडीएस की टीम ने बम को नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि नक्सली इस हफ्ते पीएलजीए सप्ताह मना रहे हैं।जिसमें वो किसी बड़ी वारदात को करने की फिराक में हैं। पीएलजीए को पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी कहा जाता है।नक्सलियों ने इस संगठन की स्थापना साल 2000 में हुई थी।इस साल पीएलजीए की 23 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।जिसमें नक्सली संगठन के लड़ाकुओं को शामिल किया जाता है।ये लड़ाकू जवानों के साथ आमने-सामने की मुठभेड़ में शामिल होते हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस पीएलजीए सदस्य गुरिल्ला आर्मी वॉर मे माहिर होते हैं।हर साल 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक अपने इन पीएलजीए के सदस्यों के मारे जाने की याद में नक्सली इस सप्ताह को मनाते हैं। आपको बता दें कि चुनाव के पहले नक्सलियों कई जगह बम प्लांट किए थे।लेकिन चुनाव के दौरान सुरक्षा जवानों की गश्ती के कारण नक्सली किसी भी बड़ी वारदात को करने में सफल नहीं हो पाए।कई बमों को वोटिंग से पहले ही फोर्स ने बरामद करके नष्ट किया था।इस दौरान चुनावी महीने में 11 नक्सल वारदात देखने को मिली है। जिसमें तीन बार नक्सल मुठभेड़ हुई।मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ।वहीं 6 ग्रामीणों की मौत हुई। वहीं सुरक्षाबल ने एक एके 47, 12 आईईडी, एक देशी रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए है।पीएलजीए सप्ताह के दौरान नक्सली बड़ी वारदातों को करने की फिराक में रहते हैं।

हथियारबंद नक्सलियों ने ग्रामीण के घर घुसकर की लूटपाट

कवर्धा। मंगलवार की देर रात नक्सलियों ने स्थानीय ग्रामीण के घर में घुसकर ग्रामीण लूटपाट की और नौ दो ग्यारह हो गये। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर सर्चिंग अभियान को और तेज किया। प्राप्त समाचारों के अनुसार कवर्धा के चिल्फी थाना क्षेत्र के गांवों में हथियारबंद नक्सलियों ने एक बार फिर से दस्तक दी है। करीबन एक दर्जन हथियारबंद नक्सलियों ने ग्राम बहनाखोदरा में एक ग्रामीण के घर रात घुसे और बंदूक की नोंक पर ग्रामीण को धमकाया। मारपीट कर नक्सलियों ने कहा कि पुलिस का साथ दिया तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद घर से रखे खाने पीने का सामान अनाज व मुर्गा-बकरा लूटकर जंगल की ओर भाग निकले।

संयुक्त संचालक शिक्षा के पद पर रहे रामानंद हीराधर को गिरफ्तारी वारंट जारी

आय से अधिक संपत्ति का है मामला

बिलासपुर। बिलासपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व बिलासपुर संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा के पद पर रहे रामानंद हीराधर के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले में जिला न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में चालान जिला न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद अदालत ने पूर्व संयुक्त संचालक शिक्षा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

बिलासपुर संभाग के संयुक्त संचालक रामानंद हीराधार बिलासपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर भी रहे थे। इस दौरान आय से अधिक संपत्ति बनाने के मामले में उनकी शिकायत हुई थी। मामले में जांच के बाद कुल 1 करोड़ 43 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर के निरीक्षक सी तिग्गा को प्रार्थी बनाकर 24 जून 2021 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (बी) व 13 (2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। रामानंद हीराधर ने अपने पद का फायदा उठा भ्रष्टाचार कर अपनी अपनी पत्नी व अपने दोनो बच्चों के नाम से कांकेर जिले के टिकरा व मानकेसरी गांव, रायपुर के अभनपुर, बायरन बाजार बिलासपुर के चांटीडीह, द्द्ध व मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की रकम की जानकारी जांच में मिली थी।

पर्याप्त साक्ष्य के बाद भी आरोपी हीराधर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जल्द से जल्द जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में जानकारी दी गई थी कि एसीबी में बार-बार आवेदन देने के बाद भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने एसीबी के एसपी को 6 सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर सीआरपीसी की धारा 173/2 के तहत ट्रायल कोर्ट में चालान जमा करने के निर्देश दिए थे।

अदालत के आदेश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच पूरी कर बिना गिरफ्तारी के ही विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सुनील कुमार जायसवाल की अदालत में आरोपी आरएन हीराधार के खिलाफ चालान पेश किया। चालान पेश होने के बाद अदालत ने आरोपी आरएन हीराधार की गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। वहीं गिरफ्तारी वारंट की जानकारी लगते ही आरोपी संयुक्त संचालक शिक्षा रहें रामानंद हीराधर ने अग्रिम जमानत याचिका भी प्रस्तुत कर दी है। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत में 7 दिसंबर को होने वाली है।

कई विधानसभा सीटों में नोटा तीसरे स्थान पर आदिवासियों को ज्यादा पसंद आया नोटा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा को 54, कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली है। दोनों चरणों में मतदान प्रतिशत 76।30 प्रतिशत रहा। कुल 1 करोड़ 55 लाख 61 हजार 460 मतदाताओं ने मतदान किया। जिनमें 77 लाख 48 हजार 612 पुरुष मतदाता और 78 लाख 12 हजार 631 महिला मतदाता हैं। कुल मतदाताओं में से 1।26 प्रतिशत यानी 197678 वोटर्स ने नोटा को अपना वोट दिया। जो जेसीसीजे को छत्तीसगढ़ में मिले कुछ वोटों से ज्यादा है। जेसीसीजे को इस साल हुए विधानसभा चुनाव में 1.23 प्रतिशत वोट मिले। यानी कुल 192406 वोट।

हालांकि छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनावों में नोटा वोट शेयर 2013 और 2018 के चुनावों की तुलना में काफी कम था। 2018 में 4.1 लाख से ज्यादा मतदाताओं और 2013 में 2.82 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना था। साल 2018 में नोटा को ज्यादा वोट मिलने के बावजूद, जेसीसीजे और बीएसपी गठबंधन ने सात सीटें हासिल की। आप को इस बार चुनाव में 0.93 प्रतिशत, सीपीआई को 0.39 प्रतिशत, सीपीआई-एम को 0.04 प्रतिशत, बीएसपी को .05 प्रतिशत, एसपी को 0.04 प्रतिशत, एलजेपी को 0.00 प्रतिशत, एलजेपीआरवी को 0.01 प्रतिशत और अन्य को 5.55 प्रतिशत वोट मिले।

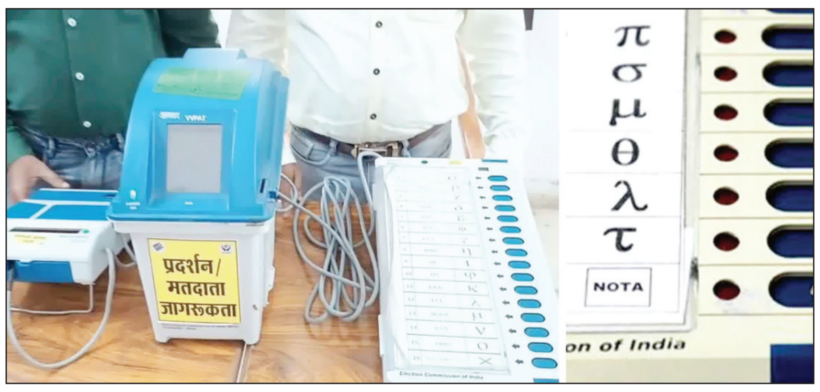

छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभा क्षेत्रों में नोटो को सबसे ज्यादा वोट मिले। इनमें से बस्तर संभाग के 6 विधानसभा सीट बस्तर, बीजापुर, चित्रकोट, जगदलपुर, केशकाल और कोंडागांव ने नोटा वोटों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर सीपीआई उम्मीदवार ने नोटा को कड़ी टक्कर देते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। यहां सीपीआई उम्मीदवार भीमसेन मंडावी को 9217 वोट मिले जबकि नोटा को 8260 वोट मिले। कई राउंड्स में नोटा तीसरे स्थान पर रहा।

चित्रकोट को सबसे ज्यादा 7310 नोटा वोट, केशकाल में 4335 नोटा वोट, बिंद्रानवागढ़ में 3710 नोटा वोट, बीजापुर में 3628 नोटा वोट, साजा में 3600 नोटा वोट, रामानुजगंज में 3501, धरमजयगढ़ में 1714, मोहलामानपुर में 3354 नोटा वोट, कोंडागांव में 3214, लुंड्रा 2906, जगदलपुर 2836, कुरुद 2756, बस्तर 2738, धमतरी 2695 नोटा वोट, कुनकुरी 2532 नोटा, लैलुंगा 2328, खैरागढ़ 2312, आरंग 2255, अभनपुर- 2087 नोटा वोट, बसना 1443 नोटा वोट। ईवीएम में नोटा यानी None of The Above का विकल्प मतदाताओं के लिए रखा गया है। 2014 में राज्यसभा चुनावों में नोटा का पहली बार प्रयोग किया गया। नोटा बटन दबाकर वोटर ईवीएम में दिए गए किसी भी प्रत्याशी को वोट ना देने का अधिकार देता है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भाजपा प्रत्याशी की हार पर मुंडवाया आधा सिर और मूंछ

महासमुन्द। महासमुंद में चुनाव के दौरान कुछ दिलचस्प चीजें भी सामने आती हैं उनमें से एक अजीबो गरीब शर्त लगाना भी शामिल है। इस बार के विधानसभा चुनाव में महासमुंद जिले की खल्लारी विधानसभा में जीत हार को लेकर हैरान करने वाली शर्त लगी। शर्त लगाने वाले भाजपा कार्यकर्ता ने शर्त हारने के बाद अपने वादे को निभाया और लोगों में आकर्षण का केंद्र बन गया। खल्लारी विधानसभा के ग्राम बिहाझर के रहने वाले 48 वर्षीय डेरहा राम यादव, जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करते है। उन्होनें ने खल्लारी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अल्का चंद्राकर की जीत का दावा करते हुए अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि अल्का चंद्राकर के चुनाव हारने पर वह अपने सिर के आधे बाल और आधी मूंछ साफ करा लेंगे। इसके बाद चुनावी नतीजों में अल्का चंद्राकर की हार के बाद डेरहा राम ने अपना वादा पूरा किया और सुर्खिया का केंद्र बन गए। डेरहा राम यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। डेरहा राम का कहना है कि हम कांग्रेस की तरह वादाखिलाफी करने वालों में से नहीं है।

बलरामपुर में नालियों की सफाई में लगे कांग्रेस पार्षद

बलरामपुर। नगर पंचायत राजपुर के कांग्रेसी पार्षद पुरनचंद जायसवाल का एक वीडियो सेशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियों में कांग्रसी पार्षद खुद ही सफाई करने नाली में उतर गए और कुदाल से नाली की सफाई करने लगे। इस घटना का वीडिया अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस के पार्षद पुरनचंद जायसवाल का कहा, यहां नालियों की सफाई नहीं होती, जिससे मोहल्ले में बदबू आती है। सड़कों पर गंदगी पड़ी रहती है। मेरे पास शिकायत करने मोहल्ले के लोग पहुंचते हैं। मैं इस वार्ड का पार्षद हूं, जनता ने मुझ पर भरोसा करते हुए पार्षद के रूप में चुना है। इसलिए सफाई की जिम्मेदारी मैंने खुद ही अपने कंधों पर उठा लिया और नालियों की सफाई कर रहा हूं। ताकि सीएमओ की आंख खुले तो यहां साफ-सफाई कराएं। नाली की सफाई करने खुद उतरे कांग्रेसी पार्षद- पुरनचंद जायसवाल, बलरामपुर में नगर पंचायत राजपुर के वार्ड क्रमांक 04 से कांग्रेसी पार्षद हैं। पुरनचंद जायसवाल आज सुबह कुदाल लेकर नाली की सफाई करने खुद ही उतर गए।

लगातार हो रही बारिश से ढ्हा किसान का घर

जशपुर। चक्रवाती तूफान मिचौंग का असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण जशपुर जिले में एक किसान का घर ढह गया। हादसे में घर में सो रहे 4 सदस्य मलबे में दब गए, जिससे वे घायल हो गए हैं। घटना आज भोर में बगीचा विकासखंड के बुरजूडीह गांव में हुई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही गांव के पूर्व सरपंच बुधेश्वर पैकरा मौके पर पहुंचे। फिर ग्रामीणों की मदद से तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और मलबे में दबे सभी सदस्यों को बाहर निकाला गया। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि, मिचौंग तूफान के कारण मंगलवार से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। इसकी वजह से राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। वहीं ठंड बढ़ गई है। मौसम में हुए परिवर्तन ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग की अनुसार आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी।

मिचोंग तूफान ने मचाई तबाही बस्तर में मचा त्राहि माम !

जगदलपुर। दक्षिण भारत में तबाही मचाने वाले मिचोंग चक्रवर्ती तूफान का असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर, धमतरी, कवर्धा के साथ बस्तर में भी पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश से बस्तर में ठंडी हवाएं भी चलने लगी है। वहीं दूसरी ओर बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।क्योंकि इस बारिश के कारण किसानों का धान भी खराब होने लगा है। मीडिया से बातचीत के दौरान एक किसान ने बताया कि, फसल काटकर अपने घर ले आए हैं। धान की मिसाई हो गई है। कई लोगों ने तो धान की मिसाई भी नहीं की है।मिसाई के बाद धान केन्द्रों में धान बेचने जाते हैं। लेकिन इस साल अचानक बारिश हो गई। बारिश के कारण घर में रखा धान भीग गया है। वैसे तो धान को तिरपाल से ढक दिए हैं। लेकिन बारिश इतनी तेज है कि तिरपाल के भीतर का धान भी भीग सकता है।

महादेव एप घोटाले के आरोपी के पिता की मौत

दुर्ग। महादेव सट्टेबाजी एप घोटाले में आरोपी नामित व्यक्ति के पिता मंगलवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। पुलिस के मुताबिक अंडा थाना क्षेत्र के अछोटी गांव के कुएं में एक बुजुर्ग का उतराता शव मिला है। बुजुर्ग की शिनाख्त सुशील दास के रूप में हुई है। सुशील दास फॉर्म हाउस में चौकीदारी करता था। मृतक पिछले दिनों महादेव सट्टा एप मामले में गिरफ्तार असीम दास के पिता बताये जा रहे हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर कुएं से शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद से वह काफी दिनों से परेशान थे और शराब का सेवन कर रहे थे। अंडा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक असीम दास के पिता सुशील दास करीब पांच साल से अंडा थाना क्षेत्र के ग्राम अछोटी में रूपेश गौतम के फार्म हाउस में चौकीदारी का काम करते थे। वह फार्म हॉउस में बने कमरे में ही रहते थे।

प्रदेश में जिसकी सरकार बनी उस पार्टी का नहीं मिला विधायक

■ धमतरी में परंपरा कायम, इस बार ओंकार ने भाजपा विधायक रंजना को हराकर कायम रखा इतिहास

धमतरी। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और इसका परिणाम भी अब सामने आ चुका हैं। 2018 के उलट 2023 में भाजपा फिर से सत्ता में वापस हो चुकी है और इसके लिए प्रदेशभर में जश्न भी मनाया जा रहा है, लेकिन अगर धमतरी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां 2023 में कांग्रेस के प्रत्याशी ओंकार साहू ने जीत हासिल की है।

धमतरी के चुनावी इतिहास को देखें और उसके परिणामों को देखें तो इस चुनाव परिणाम के बाद भी धमतरी के लोगों में निराशा ही हाथ आई है। इसका कारण इस चुनाव के परिणाम में तो है ही, लेकिन सन 2000 से लेकर 2023 तक जो पांच विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके परिणाम भी निराशाजनक रहे हैं। इसके पीछे बड़ा कारण है धमतरी के चुनावी इतिहास में यह लगातार पांचवीं बार हुआ है कि जिस पार्टी की सत्ता प्रदेश में आकर बैठी है उस पार्टी का विधायक धमतरी विधानसभा को नहीं मिल सका है। यही कारण है कि अब तक यहां का विकास ठीक से नहीं हो पाया है।

धमतरी में अगर विकास के नहीं होने के आरोप लगते हैं तो आम जनता के मन में फिर से वही बात आती है कि जिस पार्टी की सत्ता होती है उसका विधायक नहीं मिल पाता और इसी कारण धमतरी का विकास भी नहीं हो पाता।

धमतरी के इतिहास की बात करें तो सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब यहां पर कांग्रेस की सत्ता थी और अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने, उसी समय यहां के विधायक कांग्रेस के हर्षद मेहता थे। वर्ष 2003 में चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में आई और इंदर चोपड़ा भाजपा के यहां से विधायक चुने गए, लेकिन 2008 के चुनाव में फिर से भाजपा सत्ता में आई और कांग्रेस के गुरमुख सिंह होरा विधायक बने। 2013 में भाजपा सत्ता में लौटी और फिर से गुरमुख सिंह होरा विधायक बने। 2018 में सरकार बदली कांग्रेस सत्ता में आई लेकिन धमतरी की विधायक भाजपा की रंजना साहू बन गई। अब 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है और इधर धमतरी के विधायक कांग्रेस के ओंकार साहू बन गए हैं। इन परिणामों के बाद धमतरी के लोगों का एक ही कहना है कि जब तक सत्ताधारी दल का विधायक ना मिले तब तक कहीं ना कहीं विकास अपनी गति से नहीं हो पाता, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है।

धमतरी का इसे भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, जनता के मन में निराशा स्पष्ट नजर आती है। हमने धमतरी के जागरूक बुद्धिजीवी वर्ग से बातचीत करने की कोशिश की तो सभी का आकलन और विश्लेषण यही कहता है कि जब तक सरकार किसी की भी बने, लेकिन जिसकी जिस पार्टी की सरकार बने उसका ही अगर विधायक मिले तो कहीं ना कहीं धमतरी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। जब तक ऐसा नहीं हो पाएगा तब तक लोगों को विकास के लिए तरसना ही पड़ेगा।

राजनांदगांव में डाक विभाग का संभाग खोलने लोकसभा में सांसद पांडेय ने उठाया मुद्दा

कबीरधाम। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री संतोष पांडेय ने बुधवार को लोकसभा में राजनांदगांव में डाक विभाग का संभाग नहीं होने से होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाया और राजनांदगांव को डाक विभाग का संभाग बनाने की मांग की।

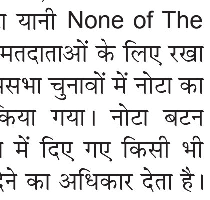

सांसद संतोष पांडेय ने लोकसभा में विभागीय मंत्री से मांग करते हुए कहा कि राजनांदगाँव मे डाक विभाग का उपसंभाग है, किंतु संभागीय कार्यालय अन्यत्र जिला भिलाई (दुर्ग) मे होने के कारण राजनांदगांव जिला सहित पास लगे हुए अन्य जिले व लोकसभा क्षेत्र के नागरिक एवं कर्मचारी डाक विभाग से संबंधित कार्य हेतु भिलाई (दुर्ग) पर निर्भर रहते है। डाक संभाग कार्यालय दूरस्थ होने के कारण आम जनता का समय और आवागमन में पैसा दोनो बर्बाद होता है। महोदय जी अवगत कराना चाहता हूँ कि गत दिनों मेरे संसदीय क्षेत्र के जिलों की संख्या 02 से 04 हो गई है। जिसमे 01 जिला पूर्णता आदिवासी जिला है। राजनांदगांव उपसंभाग अंतर्गत वर्तमान मे जिला कबीरधाम, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, जिला मोहला-मानपुर-चौकी जो कि पूर्णता आदिवासी जिला भी है, विकासखंड डोंगरगढ़ व डोंगरगांव, उपसंभाग के रूप मे कार्यरत है। उक्त सभी उपसंभाग की दुरी राजनांदगांव जिला मुख्यालय से समीप है, किन्तु वर्तमान सम्भ्गीय कार्यालय की औसत दुरी सभी जिलो से 120 किमी है। उक्त उपसंभागो को जोड़कर राजनांदगांव को पूर्ण संभाग का दर्जा देने दिया जाए। संभाग बन जाने से डाक विभाग से संबंधित समस्त कार्य राजनांदगांव से होने लगेगा तथा सम्पूर्ण कार्य में अनावश्यक विलंब ना होकर कार्य त्वरित गति से होने लगेगा।

रमन सिंह के अलावा इन चेहरों पर दांव लगा सकती है भाजपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 54 सीटों पर भागवा लहराया है। जबकि साल 2018 में 68 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बिना किसी चेहरे के विधानसभा चुनाव में उतरी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा? पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई बड़े चेहरे हैं जो सीएम की रेस में शामिल हैं। अब देखने वाली बात ये होगी की पार्टी किस चेहरे पर दांव लगाती है। आपको बताते हैं पांच बड़े चेहरों के बारे में जो छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस में शामिल हैं।

पूर्व सीएम रमन सिंह

छत्तीसगढ़ के लगातार तीन बार सीएम रहे रमन सिंह राज्य में भाजपा का बड़ा चेहरा है। रमन सिंह 15 साल सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस बार चुनाव में सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी। पीएम मोदी ने खुद कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए जनता से कहा था कि कमल का फूल ही भाजपा का चेहरा है।

केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह

भारत सरकार में मंत्री रेणुका सिंह आदिवासी समाज से आती हैं। उनको पार्टी ने भरतपुर सोनहत सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। रेणुका सिंह ने कांग्रेस के गुलाब कमरो को हराकर विधानसभा पहुंची हैं। साल 2003 में वो पहली बार विधायक चुनी गई थीं।

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल

छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल भी सीएम पद की रेस में हैं। अग्रवाल लगातार विजय पताका फहराते जा रहे हैं। रायपुर दक्षिण सीट से बृजमोहन अग्रवाल 8वीं बार चुनाव जीते हैं। बृजमोहन अग्रवाल रमन सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे हैं।

सांसद अरुण साव

छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव भी सीएम की रेस में शामिल हैं। माना जा रहा है कि अगर डॉ. रमन सिंह को मौका नहीं मिलता है तो अरुण साव को सीएम बनाया जा सकता है। फिलहाल अरुण साव बिलासपुर से सांसद हैं। साव लोरमी सीट से चुनाव भी जीत गये हैं। अरुण साव ओबीसी समुदाय के साहू समाज से आते हैं।

बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी

प्रदेश में लता उसेंडी बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा हैं। साल 2003 में पहली बार विधायक बनी थीं उसेंडी दो बार विधायक रही हैं और दो बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। उसेंडी भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। उनका नाम भी सीएम की रेस में शामिल है।

आदिवासी महिला चेहरे पर दांव लगाएगी भाजपा?

छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। पांच साल बाद भाजपा ने सत्ता में वापसी की है। अब सवाल ये है कि राज्य की कमान भाजपा किस नेता को सौंपती है। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत तमाम नेता सीएम पद की रेस में हैं, लेकिन एक और नाम है जो सीएम पद की रेस में शामिल है और वो नाम है रेणुका सिंह का।

रेणुका सिंह फिलहाल भारत सरकार में केन्द्रीय राज्य मंत्री हैं। रेणुका सिंह प्रदेश की भरतपुर सोनहत सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। रेणुका सिंह ने कांग्रेस के सीटिंग एमएलए गुलाब कमरो को हराया है, रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिला विधायक का एक बड़ा चेहरा हैं।

रेणुका सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत जनपद पंचायत चुनाव से हुई थी। 1999 में वो पहली बार जनपद पंचायत की सदस्य चुनकर राजनीति में आईं। उसके बाद सन 2000 में बीजेपी ने उनको रामानुजनगर मंडल का अध्यक्ष बना दिया और साल 2002 में समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहने के साथ ही रेणुका सिंह 2003 में पहली बार सरगुजा संभाग की रामानुजनगर विधानसभा से विधायक चुनी गई। रेणुका सिंह दूसरी बार साल 2008 में विधायक बनीं। रेणुका सिंह स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री रहीं और सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष भी रहीं। रेणुका सिंह ने साल 2019 मे सरगुजा संसदीय क्षेत्र से सांसद बनीं और मोदी सरकार में जनजातीय मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री हैं।

रेणुका सिंह का जन्म पांच जनवरी 1964 को कोरिया जिले के पोडी बच्चा गांव में हुआ था। फूल सिंह की बेटी रेणुका सिंह का विवाह पड़ोसी जिले सूरजपुर के रामानुजनगर इलाके के रहने वाले नरेंद्र सिंह से हुआ। रेणुका के दो बेटे और दो बेटियां हैं। बेटियों का नाम पूर्णिमा सिंह और मोनिका सिंह है और बेटे यशवंत सिंह और बलवंत सिंह हैं। स्नातक तक शिक्षा प्राप्त रेणुका सिंह तेज तर्रार छवि वाली नेता मानी जाती हैं।

रेणुका सिंह पहुंची चाय वाले बाबा से आशीर्वाद लेने

जांजगीर-चाम्पा। केंद्रीय राज्यमंत्री और भरतपुर सोनहट विधायक रेणुका सिंह बुधवार को बिर्रा पहुंचीं और चाय वाले बाबा के नाम से चर्चित नरेंद्र नयन शास्त्री से आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने पूजा-अर्चना कर भागवत कथा का आनंद लिया और व्यासपीठ पर मत्था टेका। इस अवसर पर भाजपा के कई नेता उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

पूर्व सीएम ने अधिकारियों को चेताया फाइलों को बैकडेट पर स्वीकृत न करें

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने फाइलों से छेड़छाड़ के मामले में बड़े अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है। इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रदेश के कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण फाइलों को बैकडेट पर स्वीकृत कर रहे हैं, जो कि पूर्णत अनुचित है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सभी अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि आप प्रशासनिक व्यवस्था के हिस्से हैं और जब तक प्रदेश में नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक ऐसे किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य करने से आप सभी को बचना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय व इंद्रावती भवन के कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ पुरानी तारीखों में फाइलों को स्वीकृत कराने की शिकायत पहुंची है। रमन सिंह के ट्वीट के बाद इंटनेट मीडिया पर उनके प्रशंसकों ने ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की बात लिखी है।

महंत बन सकते हैं नेता प्रतिपक्ष

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद अब कांग्रेस में इस बात को लेकर कवायद शुरु हो गई है कि नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जायेगा। वैसे 35 विधायकों की संख्या एक मजबूत विपक्ष की उपस्थिति सदन में दिखाने पर्याप्त है,लेकिन यह भी जरूरी होगा कि मुद्दों पर सरकार को घेरने की,सदन में अनुभवी नेताओं की ओर पलटे तो वरिष्ठता के लिहाज से भूपेश बघेल व डा.चरणदास महंत का नाम ही दिखता है। लेकिन अभी तक कोई पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पद का निवर्हन नहीं किया है। बघेल भी यह जिम्मा निभायेंगे नहीं लगता। बचे चुनिंदा नामों में कवासी लखमा,लखेश्वर बघेल या उमेश पटेल में वो क्षमता नहीं दिखती। ऐसे में सर्वमान्य नाम महंत का ही सामने आता है। वैसे भी अपने इलाके में कांग्रेस की शानदार विजय के बाद महंत का कद पार्टी में बढ़ा हुआ है। सदन के भीतर विषयों के अच्छे जानकारी भी हैं महंत। फिलहाल अभी तय नहीं है कि पार्टी विधायकों की बैठक कब होती है।

कन्हैया मिले बृजमोहन अग्रवाल से

रायपुर। दक्षिण विधानसभा से निर्वाचित विधायक बृजमोहन अग्रवाल से सत्यमेव जयते फ़ाउन्डेशन के अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल ने मिलकर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने श्री अग्रवाल से पुरानी बस्ती क्षेत्र को धार्मिक कारीडोर बनाने की मांग की। श्री अग्रवाल ने कन्हैया अग्रवाल को इस पर शीघ्र पहल करने की बात कही। इस अवसर पर हरिवल्लभ अग्रवाल भी थे।

बुलडोजर कार्रवाई के साथ मूणत ने उठाया सवाल

▪ यह अधिकारियों की थी जिम्मेदारी, किसका था उन पर दबाव

रायपुर। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर विधायक राजेश मूणत ने कहा कि बीजेपी का मत स्पष्ट है कि शहर विकसित प्लानिंग के साथ बसना चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, उन पर किसका दबाव था, कौन इस प्रकार के कामों को संरक्षण देता था?

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि हमने भय मुक्त प्रशासन की बात कही थी। जनता का सम्मान होना चाहिए। चौराहे पर, अड्डे पर, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था। माता-बहनें जब निकलती तब किसी जाति समाज की नहीं होती। अलग-अलग कमेंट्स किए जाते थे। हमने विपक्ष में रहते हुए सरकार को सचेत करने का काम किया था।

चौपाटी प्रदर्शन पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन लेने वाले सवाल पर राजेश मूणत ने कहा कि सरकार और निगम की तरफ से क्या जवाब दिया गया देखेंगे। किस चीज की जल्दी थी। इतने बड़े पद पर बैठे हैं। नियम, कानून-कायदे सबके लिए हैं। हमने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास।

राजतिलक की तैयारी वाले पोस्टर पर राजेश मूणत ने कहा कि राजतिलक की तैयारी करनी है, सरकार आ गई है। हम गंगाजल की कसम खाने वाले नहीं, हम कर के दिखाने वाले लोग हैं। वहीं कांग्रेस के भविष्य को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बंटवारे को लेकर लड़ाई होगी।

मूणत के बयान पर उपाध्याय का पलटवार

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में रायपुर पश्चिम से प्रत्याशी रहे विकास उपाध्याय ने विधायक चुनाव हारने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, जनता ने जो जनादेश दिया है, उस पर काम करेंगे, बैठक करेंगे समीक्षा करेंगे। कहां चूक हुई है उस पर भी समीक्षा करेंगे। 5 साल हमने भूपेश बघेल सरकार में काम किया है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम किया है, अब जनता ने हमें जनादेश दिया है, 5 साल हम विपक्ष के रूप में आगे काम करेंगे। विकास उपाध्याय ने कहा, भाजपा की विचारधारा धर्म से धर्म को और भाई से भाई को लड़ाना है। अधिकारियों की सक्रियता पर भाजपा नेता राजेश मूणत के बयान पर पूर्व संसदीय सचिव व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, कांग्रेस ने कभी गलत काम का संरक्षण नहीं किया। कांग्रेस ने सत्ता का घमंड नहीं किया, हालांकि गलत चीजों को हटाना चाहिए, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुश्मनी ना निकाली जाए। सही काम करेंगे तो जनता भी आपका समर्थन करेगी। हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। बुलडोजर कार्रवाई पर राजेश मूणत के बयान पर उपाध्याय ने कहा कि, भाजपा की सोच इसी तरह की है। 15 साल तक उन्होंने कितने लोगों का मकान तोड़ा। भाजपा के चुनाव जीतने के बाद क्राइम रुकना था, लेकिन दो दिनों के भीतर फिर क्राइम की घटना हुई। भाजपा की विचारधारा धर्म से धर्म को लड़ाना है, भाई से भाई को लड़ाना है।

सांसद अरुण साव और गोमती साय ने दिया इस्तीफा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इस चुनाव में बीजेपी ने कई सांसद को भी टिकट दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी सीट पर जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सभी सांसद आज बुधवार को सांसद पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इस दौरान सांसद अरुण साव और सांसद गोमती साय आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास अपना इस्तीफा सौंपने पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद अपना-अपना इस्तीफा दे दिया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने लोरमी विधानसभा सीट से सांसद अरुण साव को टिकट दिया था। सांसद साव ने इस सीट पर बीजेपी का परचम लहरा दिया है। वे इस सीट से जीत हासिल कर मुख्यमंत्री पद के रेस में हैं। इसलिए, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। फिर अपना इस्तीफा दे दिया। इसी क्रम में सांसद गोमती साय ने भी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। वो पत्थलगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी, जहां बीजेपी प्रत्याशी साय ने चुनाव जीतने में सक्षम रही। वो भी दिल्ली पहुंचकर आज बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास अपना इस्तीफा सौंप दी है। वहीं एक तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिला सशक्तिकरण को ओर फोकस जमाये हुए हैं। ऐसे में चर्चा है कि गोमती साय के इस इस्तीफा के बाद सीएम चहरे के लिए हल-चल तेज हो गया है।

चुनाव में हार के बाद पीसीसी चीफ बोले- जनता का जनादेश स्वीकार

मजबूत विपक्ष के साथ जनता की बनेंगे आवाज : दीपक बैज

रायपुर। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, हमें जनता का जनादेश स्वीकार है। जनता ने हमें जो आशीर्वाद दिया है इसका हम सम्मान करते हैं। भाजपा के झूठ के सामने हमारा सच दब गया। चुनाव परिणाम से हम निराश हैं, लेकिन हताश नहीं हैं। हम वापस मैदान ए जंग में उतरेंगे।

बैज ने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता को पांच साल तक सभी वादे मिले, हमें इंतजार रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल ईमानदारी से काम किया। महिला माता बहने हो, या अनसूचित जाती हो, सभी वर्ग को साथ लेकर चलने का किया है। जिस हिसाब से हम लोगों ने काम किया है, हमें विश्वास था हम लोग यहां सरकार बनाएंगे। कहीं न कहीं भाजपा का झूठ भारी पड़ गया। हमारी कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम जनादेश स्वीकार करते हैं।

दीपक बैज ने कहा, हम 35 सीटों के साथ विपक्ष में रहेंगे। जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाने की बात करेंगे। हम मजबूत विपक्ष के साथ जनता की आवाज बनेंगे। कांग्रेस की हार की वजह क्या रही, इसकी समीक्षा की जाएगी। आखिर इतना अच्छा काम करने के बाद चूक कहां हुई है।

हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा को लेकर बैज ने कहा, हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े। सबके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। हाई कमान तय करेगा। बुलडोजर कार्रवाही मामले में दीपक बैज ने कहा, भारतीय जनता पार्टी डराने की राजनीति करते आई है। आईटी इड्डी ईडी के माध्य से डराने का काम कर रहे है। मैं समझता हूं लोकतंत्र में इसके लिए जगह है।

भाजपा से आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर दीपक बैज ने कहा, छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र से जनादेश प्राप्त हुआ है। आदिवासी समाज में कई अनुभवी चेहरे रहे हैं। आदिवासी कई बार विधायक, सांसद और मंत्री रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मौका देते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी।

भगत मूंछ मुड़वाने वाले बात से मुकर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए : टोप्पो

▪ मंत्री अमरजीत को पटखनी देने के बाद विधानसभा पहुंचे पूर्व सैनिक रामकुमार

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में 5 साल के वनवास के बाद भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मंत्रियों को नए चेहरों ने उखाड़ फेंका है। इसमें से एक सीतापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो हैं। राम कुमार टोप्पो ने भूपेश सरकार में मंत्री रहे अमरजीत भगत को 17160 वोटों से हराया है। जीत के बाद आज नाम दर्ज कराने विधायक रामकुमार टोप्पो छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

इस दौरान विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि मैं राजनीति में आने का सोचा नहीं था, मेरे को सीतापुर की जनता ने स्वयं पत्र लिखकर बुलाया। उनकी मांग से भाजपा ने हमें अपना प्रत्याशी बनाया और आज जीत दर्ज हुई। जनता ने क्षेत्र के तमाम समस्याओं को लिखते हुए कहा था कि आज क्षेत्र खतरे में है। मुझे सेना से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए।

मंत्री अमरजीत भगत को लेकर टोप्पो ने कहा कि चुनौतियों में नहीं मानता, शुरू से ही वहां की जनता पूर्ण रूप से हमारे साथ खड़ी थी। इसलिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। वहां की जनता चुनाव लड़ रही थी इसलिए भारी मतों से जीत कराया, जनता का जनादेश मिला है। जिम्मेदारी बड़ी है मेरे लिए वहां की जनता पहले है उनकी समस्याओं के लिए लड़ने आया हूं और लड़ूंगा।

अमरजीत भगत के कसे गए तंज पर रामकुमार टोप्पो ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे तंज किए थे, बहुत हल्के तंज किये थे। शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी वह गद्दार हैं तो मैं उनके तंज का स्वागत करता हूं। वह मूंछ मुड़वाने वाले बात से मुकर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कमिटमेंट की है तो मुड़वाना चाहिए। जनता को उम्मीद हमारे प्रति ज्यादा है, पार्टी के प्रति ज्यादा है हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। यहां की चुनौतियां थोड़ी डिफरेंट है। सेना में सुरक्षा की चुनौतियां होती है। यहां पर जनता की समस्याओं की चुनौती है।

विजय बघेल ने भूपेश पर लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

▪ छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग से की शिकायत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुके हैं। नतीजे आ गए हैं लेकिन सियासी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। ताजा मामला कार्यवाहक सीएम भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल को लेकर है। दोनों के बीच पाटन सीट पर चुनावी घमासान देखने को मिला था। अब ताजा मामला आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर है। विजय बघेल ने भूपेश बघेल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने इस बात की शिकायत छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले से मुलाकात कर की है।

भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी है। जिसमें भूपेश बघेल के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा सांसद एवं पाटन से उम्मीदवार विजय बघेल और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल शामिल थे।

विजय बघेल ने कहा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर पाटन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से अवगत कराया। दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव प्रचार पर रोक की नीयत अवधि के बाद भी पाटन में मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल द्वारा रोड शो करके प्रचार करने को गंभीरता से लिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 48 घंटे का समय कार्रवाई के लिए दिया है। मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे पत्र में बघेल ने कहा है कि हमने इस संबंध में 16 नवंबर को चुनाव आयोग को की गई शिकायत का हवाला दिया है। जिसमें चुनाव अधिकारी ने आचार संहिता के उल्लंघन नहीं होने की बात कही थी। 15 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म हो गया था। उसके बाद भी सीएम बघेल ने 16 नवंबर को चुनाव प्रचार किया। इसी बात की शिकायत की गई है। पहले शिकायत की गई थी, लेकिन उसकी सही से जांच नहीं हो पाई है। हम इस केस में दिल्ली चुनाव आयोग में गए। चुनाव आयोग में भी इसमें सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम दिल्ली हाईकोर्ट गए फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने हमें निर्देश दिया कि आप एक बार फिर राज्य चुनाव आयोग के पास जाइए। फिर हम यहां आए हैं अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम फिर कोर्ट जाएंगे।

विजय बघेल ने कहा कि 16 नवंबर, 2023 के आवेदन और 24 नवंबर, 2023 को दिए गए स्मरण पत्र के साथ अटैच वीडियो एवं दो फोटो हैं। जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी दिनांक 16 नवंबर 2023 को रोड शो के दौरान लाउडस्पीकर और गाजा बाजे का प्रयोग कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में दुर्ग के अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई है। इसलिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे गए पत्र में मांग की गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट के ताजा आदेश के आधार पर उस वीडियो की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा उस वीडियो और उसमें शामिल व्यक्तियों की जिला प्रशासन से अलग निर्वाचन आयोग से जांच कराई जानी चाहिए। निर्वाचन कार्यालय के वरिष्ठ और विशेष अधिकारी की टीम से इसकी जांच कराई जानी चाहिए और इस मामले में केस दर्ज की जानी चाहिए। विजय बघेल ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जांच के लिए 48 घंटे का समय तय किया है। अगर उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता तो हम फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इस मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

महंत को बधाई देने पहुंचे हरमीत होरा

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाने के मिथक को तोड़ते हुए डा.चरणदास महंत ने स्वंय की शानदार जीत के साथ जांजगीर चांपा,सक्ति से लेकर आसपास के विधानसभा सीट अपने प्रभाव के चलते कांग्रेस को जीत दिलवाने में सफल रहे.ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। नागरिक सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री हरमीत सिंह होरा ने आज उनसे सौजन्य भेंट कर इस जीत की बधाई दी।

कमजोर कानून व्यवस्था को करेंगे मजबूत : ईश्वर साहू

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का रिजल्ट चौकाने वाला रहा। वहीं बेमेतरा जिले की साजा सीट के परिणाम ने भी सबको अचंभित कर दिया। यहां एक मजदुर ईश्वर साहू जिन्होंने अपने बेटे को दंगे में खोया था। उन्होंने भूपेश सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को 5196 वोटों से हरा है। ईश्वर साहू की इस जीत की हर ओर चर्चा है क्योंकि उन्होंने सात बार के विधायक रह चुके रविंद्र चौबे को मात दी है। वहीं जीत के बाद आज विधायक ईश्वर साहू अपने समर्थकों के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे। विधायक ईश्वर साहू ने विधानसभा पहुंचते ही चौखट पर घुटने टेक कर प्रणाम किया।

ईश्वर साहू ने कहा कि हम हमारे क्षेत्र की जो जरूरत है वह पूरा करेंगे, जो जिम्मेदारी हो पूरा करेंगे। ईमानदारी से काम करेंगे। हमारी प्राथमिकता है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, कांग्रेस की सरकार ने जो रोक रखा था उसे जल्द से जल्द हम लागू करेंगे। मुफ्त में गरीबों को चावल देने की योजना जो रोक कर रखे थे उसे देंगे। ऐसे बहुत से काम रुके हुए हैं उसे पूरा करेंगे। जितना ज्यादा हो सके हम विकास करेंगे। इसके साथ ही कहा कि जो अपने पद की पॉवर से कानून व्यवस्था कमजोर किए हुए थे उसे दुरुस्त करेंगे, उसे मजबूत करेंगे।

विरोधियों के बेतुके बयान भी भाजपा के मददगार

बलबीर पुंज

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों के निहितार्थ क्या हैं? यह ठीक है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनता ने भाजपा की नीतियों-कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों से प्रभावित होकर बहुमत दिया है। परंतु लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बेतुके बयानों से आहत होकर भी जनता कांग्रेस के खिलाफ मत देने को विवश हो जाती है। भले ही बीते एक वर्ष से इस दल की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खरगे कर रहे है, परंतु पार्टी की परोक्ष कमान गांधी परिवार के हाथों में ही है। वर्षों से कांग्रेस में विचारधारा का टोटा है, जिसकी पूर्ति घिसे-पिटे वामपंथी जुमलों से करने का प्रयास हो रहा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण कांग्रेस द्वारा तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए राजनीति में जाति के भूत को पुनः जीवित करने का प्रयास है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा इन चुनावों में 'जितनी आबादी, उतना हक' का नारा बार-बार दोहराया गया। अभी तक सपा, बसपा, राजद जैसे क्षेत्रीय दल जाति आधारित राजनीति करते थे। यह पहली बार है, जब किसी राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस ने इस जिन्न को बंद बोतल से बाहर निकालने की कोशिश की है। जाति निश्चय ही भारतीय समाज की एक सच्चाई है। परंतु अब आधुनिक शिक्षा, सर्वांगीण अवसर, तकनीकी दौर और बाजारवाद के युग में जाति की भूमिका गौण हो गई है। आज के आकांक्षावान युवा जातीय पहचान से ऊपर उठकर देखने की क्षमता रखते हैं। इसलिए राहुल-प्रियंका के 'सत्ता में आने पर जातिगत-जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से हक दिलाने' के वादे का उलटा प्रभाव हुआ। इसी वजह से अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की योजनाओं के असंख्य लाभार्थी भी कांग्रेस से छिटक गए। इससे पहले गत वर्ष गुजरात विधानसभा चुनाव और अपनी 'भारत जोड़ो' यात्रा के समय राहुल ने आदिवासियों को देश का 'असली मालिक' बताया था। यदि राहुल के लिए आदिवासी देश के 'असली मालिक' हैं, तो शेष लोग कौन हैं? छत्तीसगढ़-मध्य प्रदेश जैसे आदिवासीबहुल राज्य में भाजपा की निर्णायक जीत ने राहुल की 'आदिवासी बनाम शेष हिंदू समाज' की राजनीति को भी ध्वस्त किया। वास्तव में, यह चिंतन भारतीय संस्कृति विरोधी वामपंथ से प्रेरित होने के साथ ब्रितानी औपनिवेशिक उपक्रम ('बांटो-राज करो' सहित) से भी जनित है, जिसका अंतिम उद्देश्य भारत को एक राष्ट्र के रूप में नकारना और उसे 1947 की भांति कई टुकड़ों में खंडित करना है। इसका प्रमाण- राहुल के विदेशी विश्वविद्यालयों में दिए उन वक्तव्यों में मिल जाता है, जिसमें उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और देश की मौलिक बहुलतावादी संस्कृति को अपमानित करते हुए कहा था—%भारत एक राष्ट्र नहीं, अपितु राज्यों का एक संघ है।% सच तो यह है कि भारत सदियों से सांस्कृतिक तौर पर एक राष्ट्र है। यह विडंबना है कि राहुल गांधी मार्क्स-मैकॉले एजेंडे को तब आगे बढ़ा रहे है, जब गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज (1909) पुस्तक में लिखा था- ...अंग्रेजों ने सिखाया है कि आप एक राष्ट्र नहीं थे और एक-राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों वर्ष लगेंगे। यह बात बिल्कुल निराधार है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे, तब भी हम एक राष्ट्र थे, हमारे विचार एक थे, हमारा रहन-सहन एक था। ...भेद तो अंग्रेजों ने बाद में हमारे बीच पैदा किए... दो अंग्रेज जितने एक नहीं, उतने हम भारतीय एक थे और एक हैं...। बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक विमर्श को भी राहुल गांधी ने सर्वाधिक क्षति पहुंचाई है। धुर वैचारिक-राजनीतिक विरोधी होने के बाद भी पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी ने सीमा नहीं लांघी। इंदिरा गांधी ने, बतौर प्रधानमंत्री, सावरकर और गोलवलकर को भी सराहा। परंतु राहुल अपवाद हैं। अपनी ही सरकार द्वारा पारित अध्यादेश की प्रति को फाड़ना, उद्यमियों को तिरस्कृत करना, एक उपनाम के सभी लोगों को चोर बताना और या 'पनौती', 'डंडे मारने' जैसे शब्दों का उपयोग करना-इसका प्रमाण है। सच तो यह है कि मोदी-शाह की जोड़ी जनता को अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रोत्साहित तो करती है, परंतु राहुल-प्रियंका के वक्तव्य कांग्रेस सरकार के लाभार्थियों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए विवश कर देते हैं।

कांग्रेस की हार, गठबंधन की मजबूती

अनिल तिवारी

उत्तर भारत के तीन प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के कस-बल थोड़े ढीले हुए है। पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा को आईएनडीआईए (इंडिया) गठजोड़ के जरिए चुनौती देने के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसे लेकर भी असमंजस बढ़ता जा रहा है। गठबंधन में शामिल दलों के दबाव में कल यानी 6 दिसंबर 2023 को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है लेकिन कई क्षेत्रीय दलों की बेरुखी को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी को इसे अनौपचारिक बैठक की संज्ञा देनी पड़ी है।

हालांकि इंडिया गठबंधन के मजबूत पैरोकार शरद पवार ने पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद कहा है कि गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन परिणाम के तत्काल बाद हो रही बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तथा गठबंधन में शामिल बड़े क्षेत्रीय दल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत व्यस्तता का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इंकार किया है। वहीं इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री जदयू नेता नीतीश कुमार के भी बैठक में शामिल होने को लेकर संदेह है।

दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन में शामिल सभी क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी से दो टूक बात कर सीटों का बंटवारा सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। क्षेत्रीय दलों को यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जिन राज्यों में जनाधार कमजोर है, उन राज्यों में भी आधिकाधिक सीट हथियाना चाहती है। लेकिन क्षेत्रीय दल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए सीट बंटवारे का मसला हल किए जाने हेतु लगातार दबाव बनाते रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के इस दबाव से वाकिफ है। इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक चुनौती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रीय दलों की ओर से लगातार मिलती रही है। इन सात राज्यों में लोकसभा की कुल 269 सीटें आती हैं। इन सातों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत कांग्रेस पार्टी से कई गुना अधिक है। खासकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में तो कांग्रेस %न% के बराबर है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के विरोध में सपा और बसपा हैं तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। तमिलनाडु और बिहार में कांग्रेस परजीवी की तरह है, तो 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना की पिछलग्गू है।

गठबंधन में शामिल सभी दल सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से बेदखल करने के लिए एकजुटता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में अपनी बड़ी भूमिका और बड़ी हिस्सेदारी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। क्षेत्रीय दल कांग्रेस की भूमिका को सीमित करते हुए जल्द से जल्द सीट का फार्मूला तय करने के लिए दबाव बना रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी अब भी पार्टी के पक्ष में माहौल बनने तक निर्णयों को टालने के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी भी भली प्रकार यह जानती है कि उसकी ही जमीन पर अपनी राजनीति चमकाने वाले क्षेत्रीय दल अवसर आने पर कांग्रेस को कमजोर करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की खटिया खड़ी कर रखी है। इन सभी राज्यों के क्षेत्रीय दलों के नेता समय-समय पर यह बताते रहे हैं कि उनके राज्य में उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर जब सपा और कांग्रेस के बीच गतिरोध बढ़ा तो लखनऊ लौटते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि समाजवादी पार्टी सीटें मांगने वाली पार्टी नहीं बल्कि सीट बांटने वाली पार्टी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त मिलने के बाद समाजवादी पार्टी और अधिक हमलावर हो रही है।

सपा प्रमुख की तरह ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी विभिन्न मौकों पर यह कहा है कि गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को एक सीमा से अधिक तवज्जो देने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान करना। कमोबेश यह सभी क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी के विरोध में जनमत तैयार कर अपनी जगह बनाए हुए हैं। इन क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पार्टी की कार्य संस्कृति का भी पूरी तरह से ज्ञान है।

ज्ञात हो कि भाजपा को पूरे देश में चुनौती देने की गरज से जब इंडिया का गठन हुआ था तब कांग्रेस पार्टी का रवैया अपेक्षाकृत मिलनसार था। लेकिन पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस के नेताओं के सुर बदलने लगे थे। कांग्रेस के बदलते तेवर देखते हुए गठबंधन में शामिल सभी दल जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा और इसकी औपचारिक घोषणा के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। गठबंधन में शामिल एक बड़े राज्य के क्षेत्रीय दल के नेता ने तो यहां तक कहा था कि अगर 15 दिसंबर तक गठबंधन की मीटिंग नहीं होती तो इस गठजोड़ का भविष्य अंधकारमय मान लिया जाना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी भी भली प्रकार यह जानती है कि उसकी ही जमीन पर अपनी राजनीति चमकाने वाले क्षेत्रीय दल अवसर आने पर कांग्रेस को कमजोर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसीलिए प्रारंभ से ही कांग्रेस पार्टी भाजपा विरोध के साथ-साथ सत्ता संतुलन को भी साधने की नीति पर काम करती रही है। इसी नीति के तहत माहौल अपने पक्ष में होने तक कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन की बैठक को टालती रही।

पार्टी को उम्मीद थी कि जिन पांच राज्यों में हाल में विधानसभाओं के चुनाव हुए उसमें पार्टी अगर बेहतर प्रदर्शन कर पाती तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रीय दलों की ओर से जो दबाव लगातार बनाया जा रहा है उसकी आंच कमजोर होगी। लेकिन चुनाव में कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित हो गई। हालांकि इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी सीटों के मामले में भले पीछे है, लेकिन मत प्रतिशत को बरकरार रखने में उसने कामयाबी हासिल की है।

लेकिन सौ टके की बात यह है कि पांच राज्यों में नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में गए भी होते तब भी शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन सरीखे नेता कांग्रेस पार्टी के आगे नतमस्तक हो जाते यह असंभव, हास्यासपद और बेसिर पैर की बातें हैं। यह सभी नेता उन दलों की अगुवाई करते हैं जो दल कांग्रेस को पटकनी देकर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। यह सभी दल कभी भी और किसी भी कीमत पर अपने-अपने राज्यों में कांग्रेस को बढ़ते हुए फूटी आंख भी देखना नहीं चाहेंगे।

पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाने के बाद गठबंधन में शामिल सभी क्षेत्रीय दल अब लोकसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी जल्दी से जल्दी पुख्ता करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी देशव्यापी मौजूदगी तथा हाल के चुनाव में प्राप्त मत प्रतिशत को आगे कर गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर खुद को कायम रखना चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गाहे बगाहे अब यह कहने लगे हैं कि हालिया चुनाव परिणाम से यह संकेत मिल रहा है कि देश की जनता खिचड़ी सरकारों से ऊपर उठना चाहती है। यह भी बताना नहीं भूलते कि उत्तर भारत के जिन तीन राज्यों में चुनाव हुए वहां छोटे दलों की दाल नहीं गली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सपा, बसपा, जदयू और आप पार्टी का खाता भी नहीं खुला।

कुल मिलाकर गठबंधन में शामिल सभी दल सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से बेदखल करने के लिए एकजुटता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में अपनी बड़ी भूमिका और बड़ी हिस्सेदारी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। क्षेत्रीय दल कांग्रेस की भूमिका को सीमित करते हुए जल्द से जल्द सीट का फार्मूला तय करने के लिए दबाव बना रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी अब भी पार्टी के पक्ष में माहौल बनने तक निर्णयों को टालने के पक्ष में है। यही कारण है कि गठबंधन की कल होने वाली बैठक को कांग्रेस अध्यक्ष ने अनौपचारिक बैठक कहा है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि बैठक में किन-किन बातों पर सहमति बनती है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

यागचूडामण्युपनिषद् (भाग-6)

गतांक से आगे...

आठ कुण्डलों वाली कन्द के ऊर्ध्वभाग में जो कुण्डलिनी शक्ति है, वह योगियों के लिए मोक्ष देने वाली तथा अज्ञानियों के लिए बन्धनकारक कही गई है। महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डियान बन्ध, जालन्धर बन्ध और मूलबन्ध को जो जानता है, वह योगी मुक्ति को प्राप्त करता है।

एड़ी से दबाव डालकर योनि (सीवन) स्थान को पीड़ित करते हुए दृढ़तापूर्वक संकुचित करे, अपान वायु को ऊपर की ओर खींचने की इस प्रक्रिया को मूलबन्ध कहा जाता है। इस प्रकार प्राण और अपान को एक में मिलाया जाता है, इससे मल-मूत्र कम हो जाता है। इस प्रकार मूलबन्ध का अभ्यास करने से वृद्ध भी युवा हो जाता है। महापक्षी (गिद्ध आदि) जिस प्रकार विश्राम के लिए (आकाश में अत्यधिक ऊँचे) उड़ते हैं, उसी तरह उड्डियान बन्ध का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है। (बड़े पक्षियों को एक विशेष प्रकार से उड़ने में विश्राम प्राप्त होता है, जिससे उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है।) पेट को नाभि के नीचे तानना अर्थात् खींचना पश्चिमोत्तान कहलाता है। वहीं पेट में यह उड्डियान बंध भी किया जाता है। जो शरीर में नीचे की ओर प्रवहमान आकाश-जल (खेचरी मुद्रा द्वारा क्षरित होने वाला) को शिरोभाग में रोककर रखता है, उसे जालंधर बंध कहते हैं, यह दुःखों और कष्टों का नाश कर देता है। जालन्धर बंध में सामने की ओर सिर झुकाकर गले से नीचे ठोढ़ी को हृदय से स्पर्श करना होता है। इससे अमृत न तो अग्नि की ओर गिरता है और न वायु की ओर गमन करता है, स्थिर हो जाता है। दृष्टि को दोनों भौंहों के मध्य स्थित करे एवं जीभ को गले की ओर पीछे लौटाकर कपाल कुहर (गले के मध्य तालु) में प्रवेश कराये, इस प्रकार की क्रिया को खेचरी मुद्रा कहते हैं।

क्रमशः ...

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस

अमृता गोस्वामी

भारत सहित दुनिया भर में हर साल 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस (इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे) मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और एकरूपता सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की आधिकारिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 7 दिसंबर, 1996 को की गई थी और तब से ही दुनिया भर में 7 दिसम्बर को 'अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस' मनाया जा रहा है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य राज्यों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए नागरिक उड्डयन के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

हमें एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य आना-जाना हो, चाहे वह व्यापार के लिए हो, सैर-सपाटे के लिए या रोजगार के लिए नागरिक उड्डयन की वजह से ही आसान हो पाया है। पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी जहां लोगों को कई-कई दिनों तक यात्राएं करना पड़ती थीं, नागरिक उड्डयन के चलते अब एक देश से दूसरे देश एक दिन में भी पहुंचा जा सकता है। यह नागरिक उड्डयन की सुविधा ही है कि अब सुबह का नाश्ता एक राज्य में, दोपहर का खाना दूसरे राज्य में और शाम का खाना किसी तीसरे राज्य में लिया जा सकता है।

आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया भर में 4 बिलियन से अधिक यात्री हर साल विमान से सफर करते हैं। 'अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन' संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है जिसकी स्थापना 1944 में शिकागो में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत कार्य करता है। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है।

विमानन संबंधित कुछ जानकारी

दुनिया की सबसे पुरानी एयरलाइन केएलएम (कोनिंक्लिज्के लुच्त्वार्ट मात्शाप्पिज एन.वी.) है जिसे रॉयल डच एयरलाइंस कहा जाता है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसकी पहली उड़ान एम्स्टर्डम और लंदन के बीच 17 मई, 1920 को हुई थी। दुनिया की पहली ऑफिशियल क्रिस्टेंड नेशनल एयरलाइंस ब्रिटेन की इम्पीरियल एयरवेज़ के जरिए 1927 में भारत से जुड़ी। भारत की सबसे पुरानी एयरलाइन 'टाटा एयर लाइंस' है जिसे 1932 में जेआरडी टाटा ने स्थापित किया गया था, यही भारत की पहली डोमेस्टिक फ्लाईट थी। 1946 में यह एयर इंडिया कहलाई। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन मार्केट है जो तेजी से विकसित हो रहा है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र वैश्विक रूप से 62 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विमान की खिड़की में एक छोटा अदृश्य छिद्र होता है जो खिड़कियों के बीच वायु के दबाव को नियंत्रित करता है और उन्हें कोहरे से मुक्त रखता है। विमान को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता।

छद्म हिन्दूवादी 'चेहरों' को आईना दिखा गया चुनाव

अजय कुमार

पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव में से हिन्दी पट्टी के तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधान सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी दल की दाल नहीं गल पाई। इन राज्यों में जिस पार्टी की जितनी 'हैसियत' थी, उसे यहां की जनता ने उस हिसाब से सबक सिखाया। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जनता दल युनाइड जैसी तमाम क्षेत्रीय पार्टियां सियासी मैदान में दम तोड़ती दिखीं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा कांग्रेस की हार की हो रही है। गांधी परिवार पर चौतरफा हल्ला बोला जा रहा है। भाजपा हमलावर है यह बात तो समझ में आती है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती जिनकी अपनी परफारमेंस इन चुनावों में किसी तरह से अच्छी नहीं थी, उनके तो दोनों हाथों में मानो लड्डू आ गया है। इन दोनों दलों के मुखिया कांग्रेस और गांधी परिवार को आईना दिखा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर ईवीएम पर सवाल उठाकर अपनी हार पर एक तरफ पर्दा डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ व्यंग्यात्मक लहजे में बीजेपी की जीत पर तंज भी कस रहे हैं।

कांग्रेस की हार से इत्तर यदि समाजवादी पार्टी की हार की बात की जाये तो 1993 में पार्टी के गठन के बाद से सपा को सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। सपा को मध्य प्रदेश से काफी उम्मीद थी, लेकिन उसे यहां मात्र 0.45 फीसदी वोट मिले। इतने कम वोट सपा को कभी नहीं मिले थे। पिछले 25 वर्षों में पहली बार सपा के कुल वोटों का आंकड़ा दो लाख भी नहीं पार कर पाया। सपा ने मध्य प्रदेश में 74 उम्मीदवार उतारे थे। इन उम्मीदरवारों के समर्थन में अखिलेश यादव ने करीब एक दर्जन सभाएं की थीं। अखिलेश के अलावा डिंपल यादव, शिवपाल यादव सहित तमाम नेता चुनाव प्रचार का हिस्सा बने थे। परंतु यहां न सपा का पीडीए कार्ड चला, ना ही जातीय जनगणना वाला दांव सही बैठा। अब अखिलेश ईवीएम पर भी सवाल खड़ा करते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका, जापान, जैसे टेक्नालाजी सम्पन्न देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। इसी तरह से बसपा को राजस्थान से काफी उम्मीद थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया था। एमपी में बसपा ने 178 और गणतंत्र पार्टी ने 50 उम्मीदवार उतारे थे। छत्तीसगढ़ में बसपा ने 53 और गोंडवाना पार्टी ने क्रमशः 53 और 37 प्रत्याशी खड़े किये थे लेकिन राजस्थान की दो सीटों के अलावा बसपा का कहीं खाता नहीं खुला, जबकि एमपी और छत्तीसगढ़ में बसपा ने पिछले चुनावों में दो-दो सीटें जीती थीं। बसपा प्रमुख राज्यों के चुनाव परिणाम को विचित्र बता रही हैं। वह अपने कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि इस अजूबे परिणाम से निराश न हों और पूरे उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जायें

खैर, बेहतर यह होता कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने की बजाय यह दल अपने गिरेबान में झांक कर देखते। अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्या जैसे नेताओं से सतानत धर्म को गाली दिलाकर वह चुनाव जीत सकते हैं तो यह उनकी गलतफहमी है क्योंकि भले ही हिन्दू समाज में अभी भी थोड़ा-बहुत जातपात दिख जाता है, लेकिन हिन्दू देवी-देवताओं को गाली के खिलाफ पूरा हिन्दू समाज एकजुट खड़ा रहता है। यही संदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजों से निकला है, जहां सनातनियों के सामने छद्म हिन्दुत्व हार गया। जिन दलों के नेता जातीय जनगणना कराये जाने की मांग करके हिन्दुओं को बांटना चाहते थे, उन्हें वोटरों ने आईना दिखा दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस ने जिस तरह से जातीय जनगणना के नाम पर हिन्दू समाज को बांटने के मंसूबे पाले थे, वह पूरी तरह से धराशायी हो गये।

बहरहाल, तीन राज्यों के विधान सभा चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को भी काफी हद तक बदल दिया है। अब यहां 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नये सिरे से इबारत लिखी जायेगी। इसी के साथ अगले वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की आईएनडीआईए गठबंधन की एकजुटता ग्रहण पड़ता नजर आ रहा है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इन चुनावों में खाता भी न खोल पाने वाली समाजवादी पार्टी अपनी धुर विरोधी बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार से खुश नजर आ रही है। सपा नेताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमले की बौछार कर दी है। एमपी चुनाव के समय सुभासपा मुखिया ओपी राजभर ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। सपा ने एमपी की 74 सीटों पर दावा ठोंका था जबकि कांग्रेस ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। दोनों पार्टियों के अलग-अलग चुनाव लड़ने की वजह से समाजवादी पार्टी तो खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन उसने कांग्रेस को नहीं जीतने दिया। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हमले की बात करें तो सपा के आधिकारिक प्रवक्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व सीएम कमलनाथ पर खूब हमला बोला था। सपा प्रवक्ता मनोज काका ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस को अखिलेश यादव को अपमान जनक शब्दों से सम्बोधित करना भारी पड़ा है। उन्होंने बताया कि कमलनाथ ने सपा मुखिया के खिलाफ अपमान जनक शब्द बोले थे। उनका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा था। वहीं सपा के एक अन्य प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन में कांग्रेस एक बड़ा दल है, उसे बड़े दिल के साथ इस गठबंधन को चलाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है कि अगर देश से भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो बड़े दल को बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा।

आज का इतिहास

1975 इंडोनेशियाई सेना ने पूर्वी तिमोर पर कांति-उपनिवेशवाद के बहाने हमला किया और 25 साल का कब्जा शुरू किया।

1988 अर्मेनिया में 6.9 तीव्रता वाले भूकंप से 25 हजार लोगों की मौत हुई और लाखों लोग बेघर हुए।

1992 संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1992 का डेविस कप जीता।

2004 हामिद करजई ने अफगानिस्तान के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।

2005 स्पैनिश अधिकारियों ने क्रोएशियाई सेना के जनरल एंटेगोविना पर कब्जा कर लिया, जो स्वतंत्रता के युद्ध के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए चाहते थे; अंततः उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

2006 नाइजीरियाई बंदूकधारियों ने नाइजर नदी के डेल्टा में एक तेल टर्मिनल पर आग लगा दी और तीन इटालियंस को बंदी बना लिया।

2007 स्वीडन में मुकदमा चलाने वाले किराने की दुकान श्रृंखला ढ्ढष्ट में व्यवस्थित खाद्य सुरक्षा अनियमितताओं के उजागर होने के बाद स्वीडन के अभियोजन पक्ष के वकील ने आपराधिक जाँच करने के लिए कहा।

2008 ग्रीक कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा एक किशोर की मौत के बाद, प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय एथेंस के माध्यम से दंगा किया।

2009 बगदाद में एक स्कूल बमबारी के कारण लगभग आठ लोग मारे गए और कम से कम 41 अन्य घायल हो गए।

2010 अमेरिकी न्यायाधीश ने कुछ अमेरिकी नागरिकों को कब्जा या मारने की सूची में रखने के खिलाफ अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया।

2011 रूसी फ़ेडरल स्पेस एजेंसी ने फ़ोबोस-ग्रंट और यिंगहुओ -1, उनके नमूना वापसी मिशन को बचाने की कोशिश करना बंद कर दिया है और अब उन्हें जनवरी 2012 तक पृथ्वी पर वापस गिरने की उम्मीद है।

2012 रूस ने अमेरिकी मैगनेट्स्की बिल को लेकर मानवाधिकारों के उल्लंघन के दोषी अमेरिकियों पर एक टाइट-टू-टेट वीजा प्रतिबंध की घोषणा की।

2013 इंडोनेशिया के बाली में विश्व व्यापार संगठन की बैठक, व्यापार समझौतों को सरल बनाने के लिए एक समझौते के साथ समाप्त होती है और यह गरीब राज्यों के लिए बाली पैकेज के हिस्से के रूप में अपने माल का व्यापार करने के लिए सरल बनाता है।

कांग्रेस जनता-जनार्दन के 'मन' से उतरी और भाजपा वापस 'मन' में उतरी

अनिल पुरोहित

सत्ता में रहकर जिन राजनीतिक विकारों का शिकार होने में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 15 साल का वक्त लगा था और जनता ने पक्का मन बनाकर उसे न केवल सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, अपितु विधानसभा में संख्याबल की दृष्टि से दयनीय स्थिति में ला दिया था, उन विकारों की शिकार कांग्रेस सत्ता में आते ही इतनी तेजी से हुई और इतनी ज्यादा हुई कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ पर असहनीय बोझ मानकर अपने मन से उतारने में जरा भी देर नहीं की और पाँच साल में जनता जनार्दन ने भाजपा को वापस अपने मन में उतारने का संकल्प साकार कर 75 पार का दंभ भरती कांग्रेस को अब तक के हुए पाँच चुनावों में सबसे न्यूनतम संख्याबल के साथ विपक्ष की भूमिका सौंप दी। इन चुनाव नतीजों ने राममनोहर लोहिया की याद ताजा कर दी जो कहते थे कि ज़िंदा क़ौमें पाँच साल इंतज़ार नहीं करतीं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव-2023 के नतीजों को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है जिसने तमाम एक्ज़िट पोल को धता बताकर भाजपा की भारी बहुमत की सरकार बनाने का एक्ज़ेक्ट पोल सामने रखकर सभी राजनीतिक पंडितों को खामोश कर दिया है।

छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस की हार सत्ता के गुमान में जनादेश के अपमान का परिणाम है। सत्तावादी अहंकार से लबरेज कांग्रेस आख़िर तक जन-मन को भाँपने में नाकारा साबित हुई और जिस चुनावी मैदान में वह टहलने के लिए उतरी थी, उस पर उसे हाँफते हुए सत्ता की चौखट से बाहर ही ढेर होते इस प्रदेश ने देखा। सरप्लस बिजली वाले छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार ने अनियमित और अघोषित बिजली कटौती को लेकर उठी आवाज को दबाने के लिए जिस फुर्ती से दो पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, वहीं से पत्रकार सुरक्षा का ढोल पीटती कांग्रेस के इरादे समझ आ गए थे, पूत के पाँव पालने में नज़र आ गए थे। मंत्रियों से लेकर विधायकों तक और कांग्रेस के नेताओं, उनके परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों तक के सत्तावादी अहंकार के प्रदर्शन का यह सिलसिला कांग्रेस के पूरे पाँच साल के शासनकाल में कभी बैंक कर्मी के साथ मारपीट, तो कभी अफसरों के साथ गाली-गलौज, धमकी-चमकी और कभी अपने निज सहायकों के सार्वजनिक अपमान और कभी महिलाओं के साथ बदसलूकी व अनाचार के रूप में चलता रहा। अपने किए वादों से मुकरने का जैसा राजनीतिक चरित्र छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने पाँच वर्षों में प्रदर्शित किया, पुलिस जवानों के परिजनों पर, वादों की याद दिलाकर भर्ती और रोजगार की मांग करते युवाओं पर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, संविदा व अस्थायी/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर आतंक का कहर बरपाया, उसने जन आक्रोश का एक ऐसा ज्वालामुखी तैयार किया कि आज उसके लावे में झुलसी कांग्रेस कराह रही है। अपनी इस नियति की पटकथा कांग्रेस के मदांध सत्ताधीशों ने खुद अपने हाथों पाँच सालों में लिखी है। सत्ता संस्थान को अपने राजनीतिक अंतर्कलह का केंद्र बनाकर सबने अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने राजनीतिक कद से भी ज्यादा बड़ा माना और नतीजा यह हुआ कि प्रदेश में न तो कानून के राज का कोई ख़ौफ़ रह गया था, न जनता की तकलीफें सत्ताधीशों और सामंती नौकरशाहों को विचलित कर रही थीं। चहुँओर माफियाओं ने जंगलराज जैसे हालात कायम कर रखे थे। बढ़ते अपराधों ने कदम-कदम पर लोगों को असुरक्षित और सशंकित कर रखा था, तीन साल की मासूम बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाएँ तक रोज वहशी दरिंदों के हाथों अपनी अस्मत को लहूलुहान होते देखने को विवश थीं पर सरकार न कुछ देखने को, न सुनने को और न ही कुछ बोलने को तैयार थी। महिला सशक्तीकरण कांग्रेस का राजनीतिक जुमला बनकर रह गया। गंगाजल की सौगंध खाकर पूर्ण शराबबंदी का किया गया वादा केवल झाँसा साबित हुआ और प्रदेश की मातृ-शक्ति इसके दुष्परिणामों की शिकार होकर अपने परिवार को टूटते-बिखरते देखती रही। यह विश्वासघात की पराकाष्ठा थी। सूखे नशे के काले कारोबार के साथ ही ऑनलाइन सट्टेबाजी की अंधी गलियों में धकेलकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता रहा, उन्हें आख़िरी के कुछ महीनों को छोड़कर उस बेरोजगारी भत्ता तक के लिए मोहताज रखा गया जिसके कसीदे पढ़ते हुए और इसके लिए बजट के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए 2018 के विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी करते समय उस समिति के प्रमुख टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी को %सर-सर% संबोधित करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया था। रोजगार मुहैया कराने के नाम पर कोरोना काल में शराब कारोबार की कोचिया बनी भूपेश सरकार ने इन प्रतिभासंपन्न युवाओं को डिलीवरी ब्वॉय बना डाला और पीएससी परीक्षाओं में घोटालों का करतब दिखाकर कांग्रेस नेताओं और बड़े नौकरशाहों के परिवार वालों को नियुक्ति दे दी और युवाओं के सपनों को चूर-चूर कर दिया।

बीते पाँच सालों में शराब, कोयला परिवहन, गौठान, गोबर, पीडीएस राशन, जमीन, रेत, प्रधानमंत्री अन्न योजना के चावल में भ्रष्टाचार और घोटालों के जितने मामले सामने आए, उसने भूपेश सरकार के राजनीतिक चरित्र को इतना दागदार कर दिया था कि अंत तक वह इसे धो नहीं सकी। महादेव एप पर पाबंदी लगाने का अधिकार अपने पास होते हुए भी प्रदेश सरकार ने उसे बंद करने का काम नहीं किया और इसके लिए भी वह केंद्र सरकार पर ही आख़िर तक ठीकरा फोड़ती रही। अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब में वह भाजपा की पूर्ववर्ती राज्य सरकार को भ्रष्ट बताने में ही लगी रही। दूसरों के दोष दिखाकर अपने दोषों को सही ठहराने की इस राजनीतिक निर्लज्जता को प्रदेश ने सिरे से खारिज कर दिया है। विडम्बना यह रही कि भ्रष्टाचार के जिन मामलों के लिए कांग्रेस के नेता और स्वयं निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व उनकी सरकार के लोग भाजपा सरकार पर हमलावर हो रहे थे, पाँच साल तक सत्ता में रहकर भी उनमें से किसी भी एक मामले की जाँच कराने का वे न तो नैतिक साहस दिखा सके, न ही राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटा सके! उल्टे, कोरोना सेस का हिसाब देने से प्रदेश सरकार मुँह चुराती रही परंतु मुख्यमंत्री बघेल समेत तमाम कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पीएम केयर की राशि को लेकर सवाल दागते रहे। केंद्र सरकार की उन जनकल्याणकारी योजनाओं को रोककर बदलापुर की राजनीति इस स्तर तक लेकर चले गए कि प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से ऐलानिया यह कहकर वंचित कर दिया कि इसमें चूँकि प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है, इसलिए इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार दे। भाजपा ने सवाल उठाया कि राजीव मितान क्लब के लिए जो पैसा प्रदेश के सरकारी खजाने से खर्च हो रहा है, वह क्या गांधी परिवार वहन कर रहा है? अपने ऊपर उठते सवालों का जवाब देने के बजाय कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार मर्यादाओं को ताक पर रखकर सियासी लफ्फाजियों के जरिए समाज को जाति. धर्म के राजनीतिक खाँचों में बाँटने का उपक्रम करती रही। जातिगत जनगणना का उछाला गया जुमला इसी अभियान की एक कड़ी था, जिसे प्रदेश की जनता ने पूरी सख्ती से नकारकर एक नई राजनीति के सूत्रपात का जनादेश दिया है। आरक्षण के नाम पर पूरे कार्यकाल में भूपेश सरकार और कांग्रेस के लोग इरादतन राजनीतिक पाखंड का प्रदर्शन कर राज्यपाल तक के पद की संवैधानिक गरिमा और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे लेकिन क्वांटीफायबल डाटा की वह फाइल राज्यपाल को नहीं सौंपी, जिसकी मांग राजभवन करता रहा। इसके अलावा सीबीआई को छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित करके और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को आईना भेजकर मुख्यमंत्री बघेल ने जिस राजनीतिक अपसंस्कृति का बीजारोपण किया था, वह भी कांग्रेस के इस पराभव की एक वज़ह रही है। प्रदेश में ईसाई मिशनरियाँ आदिवासी बहुल इलाकों में जबरिया धर्मांतरण करा रही थीं और प्रदेश सरकार आदिवासी संस्कृति और अपनी आस्था व परंपराओं की रक्षा के लिए सामने आए लोगों को ही मनमानी धाराएँ थोपकर जेल दाख़िल करती रही। भगवा झंडे के अपमान से उद्वेलित बहुसंख्यक समाज का आक्रोश कवर्धा में फूटा तो प्रदेश सरकार तुष्टीकरण पर उतर आई, बिरनपुर में लव ज़िहाद का विरोध करने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने मॉब लिंचिंग कर भुनेश्वर साहू की निर्मम हत्या कर दी और उन आरोपियों, जिनमें एक मंत्री का बेहद क़रीबी था, को बचाने के फेर में दूसरे मामले तैयार कर बहुसंख्यक समाज के युवकों को जेल में डालकर एक नए तरह का आतंकराज कायम किया गया।

इधर अपराधों की नित-नई कलंक गाथाएँ लिखी जा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ नक्सलवाद खून की नदियाँ बहाने पर आमादा हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों की मांद में जाकर इस समस्या का समाधान तलाशने की ज़द्दोज़हद कर रहे थे और नक्सलियों की धमकी से दुबकी मुख्यमंत्री बघेल की सरकार शहीदों का अंतिम संस्कार तक उनके गाँव में नहीं करा पा रही थी। एक सरकार के लिए, एक संवेदनक्षम लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था के लिए इससे अधिक शर्मनाक और क्या हो सकता था? प्रदेश पूछता रहा कि कांग्रेस और नक्सलियों के बीच यह रिश्ता क्या कहलाता है, और नक्सली भूपेश सरकार को %अपनी सरकार% बताकर टारगेट किलिंग कर भाजपा नेताओं की ज़िंदगियाँ तमाम करते रहे, बारुदी विस्फोट करके जवानों को मौत की नींद सुलाते रहे, पुलिस की मुखबिरी का शक जताकर निर्दोष आदिवासियों, नागरिकों, अफसरों-कर्मचारियों का क़त्ल-ए-आम करते रहे। कांग्रेस के लोग खुलेआम भाजपा का प्रचार करने वालों को मार डालने की धमकी देते रहे, (चुनाव के दौरान इस धमकी पर नक्सलियों ने अमल भी किया और पहले अक्टूबर में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम सरखेड़ा में बिरझू तारम और फिर नवंबर में नारायणपुर क्षेत्र में ग्राम धौड़ाई में सभा संबोधित करते हुए रतन दुबे की हत्या कर दी), खुद मुख्यमंत्री बघेल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुण्डा कहते सुने गए, पर इसे हेट स्पीच नहीं माना गया और शासन-प्रशासन हाथ-पर-हाथ धरे बैठा रहा, लेकिन सरकार के खिलाफ जब-जब सोशल मीडिया पर सवाल उठे, जब-जब सनातन धर्म को लेकर कोई पोस्ट सामने आई, भूपेश सरकार ने उसे हेट स्पीच बताकर उन सबके खिलाफ़ मामले दर्ज करवाने में कोई देर नहीं की। पाकिस्तान मुर्दाबाद या हिन्दुस्थान ज़िंदाबाद भिलाई में एक सिख युवक की निर्मम हत्या हो गई और आरोपी मृतक के शव पर नाचते रहे, परंतु इस पर कार्रवाई करते शासन-प्रशासन के हाथ-पैर फूलते नजर आए। प्रदेश का कोई इलाक़ा ऐसा नहीं बचा था जहाँ सत्ता की धौंस दिखाकर अन्याय, आतंक और अत्याचार की पराकाष्ठा नहीं की गई हो। और, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अपनों के साथ दगाबाजी करके सत्ता के गलियारों में नित-नए राजनीतिक षड्यंत्रों के जाल बुने गए ताकि कोई उनके मुकाबले अपने ऊँचे कद को साबित न कर पाए। आज कांग्रेस के वे दिग्गज, जिनकी हारने की कल्पना ख़ुद भाजपा के लोग नहीं कर पा रहे थे, चुनाव क्या यूँ ही हार गए हैं? क्या भू-पे स्कीम से नहीं जुड़ने की क़ीमत इन दिग्गज नेताओं ने चुनाव हारकर चुकाई है? वे कौन लोग थे, जो एक समुदाय विशेष के लोगों को मतदान के दिन शाम को मतदान से दूर रहने के लिए आर्थिक रुप से पुरस्कृत कर रहे थे? उन्हें मतदान से विमुख करने के लिए किसने धनराशि मुहैया कराई? ये सवाल आख़िरी तक सत्ता और संगठन के कांग्रेसी कर्णधारों का पीछा क़तई नहीं छोड़ेंगे। बात निकलेगी, ज़रूर निकलेगी और तय मानिए कि बात दूर तलक़ जाएगी भी।

प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी काम आयी

आशुतोष चतुर्वेदी

विधानसभा चुनावों में हिंदी पट्टी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को सिर माथे पर बिठाया है। प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा भाजपा की नैया पार करने में कामयाब रहा। जनता जनार्दन ने एक बार फिर मोदी के नाम पर हिंदी पट्टी के राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को भारी जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभाओं में भारी भीड़ जुट रही थी और उन्होंने जनता से कहा था कि जो वादे किये जा रहे हैं, वह उनकी गारंटी देते हैं। चुनाव नतीजे दर्शाते हैं कि जनता ने उन पर भरोसा किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। नतीजे किस करवट बैठेंगे, इसको लेकर सबकी धड़कनें तेज थीं। वैसे तो हर विधानसभा चुनाव हर दल के लिए एक चुनौती होता है और सभी दल पूरी ताकत लगाकर उसे जीतने की कोशिश भी करते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इस चुनाव में अपने शस्त्रागार से ऐसा कोई अस्त्र बाकी नहीं रखा था, जो न चला हो। हर विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जाता है। यह जुमला पुराना हो गया है। मुझे लगता है कि सांप-सीढ़ी के खेल से इसकी तुलना उपयुक्त होगी। 2024 से पहले का हरेक विधानसभा चुनाव आपको लोकसभा चुनाव की ऊपरी सीढ़ी के नजदीक ले जाता है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और सीढ़ी सफलतापूर्वक चढ़ गये हैं। इसके बाद 2024 की लोकसभा की सीढ़ी थोड़ी आसान हो जायेगी। हालांकि यह भी सही है कि कई बार लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजे एकदम उलट आते देखे गये हैं, लेकिन अब बहुत समय नहीं बचा है। इन विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनाव की बारी है। इस दृष्टि से मौजूदा नतीजे और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि विधानसभा चुनावों के नतीजे पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डालेंगे। इन विधानसभा चुनावों में असफलता ने विपक्ष और खासकर कांग्रेस की राह मुश्किल कर दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी कोई कमाल नहीं दिखा पायी। कांग्रेस के लिए दो सरकारों- राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चला जाना एक बड़ा झटका है। हालांकि तेलंगाना की जीत ने उसे थोड़ी राहत दी है।

राजस्थान में गहलोत और पायलट की तनातनी ने पहुंचाया नुकसान

गंगा सहाय मीणा

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलना राज्य की जनता की उस मूलभूत प्रवृत्ति को दिखाता है, जिसमें उसकी समस्याएं अनवरत बनी रहती हैं और वह अपने कष्ट के लिए वर्तमान सरकार को जिम्मेदार मानती है तथा उनसे मुक्ति के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगभग हर बार विकल्प बदलती है। निवर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने यूं तो कई महत्वपूर्ण काम किये, मसलन पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना, प्रति परिवार 100 यूनिट बिजली फ्री देना और किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री देना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख तक के इलाज को मुफ्त कर देना और बीमा उपलब्ध कराना और इसी तरह कई जन उपयोगी योजनाएं, लेकिन राजस्थान की जनता ने फिर भी उनके कामों के प्रति विश्वास नहीं जताया, इसके गंभीर विश्लेषण की आवश्यकता है।

राजस्थान सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सामंती जकड़नों में फंसा हुआ प्रदेश है, इसलिए यहां पर नयी राजनीति के लिए जगह बनाना हमेशा मुश्किल होता है और पारंपरिक रूप से यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही शासन करती आयी हैं। ये दोनों दल भी नये प्रयोगों के बहुत पक्षधर नहीं होते और अपने केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर चुनाव और सरकार संचालित करते हैं। पूरे देश की तरह राजस्थान में भी एक तबका है, जो सामाजिक समरसता और सभी के प्रतिनिधित्व का समर्थक है और एक दूसरा तबका है जो 'राष्ट्र प्रथम' का नारा देते हुए राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को वापस लाने का वादा करता है। इन दोनों के बीच राजस्थान की जनता को जब चुनना होता है, तो वह सामान्य तौर पर राजस्थान और भारत के गौरव के साथ खड़ी होती है, लेकिन सामाजिक समरसता के अपने संकल्प को साथ लेते हुए।

ये चुनाव परिणाम इस तरफ साफ संकेत कर रहे हैं कि

राजस्थान की जनता अपने बच्चों के लिए समय पर नौकरी भी चाहती है और इस मोर्चे से पर गहलोत विफल रहे हैं। सामान्य तौर पर कोई भी भर्ती प्रक्रिया तीन-चार साल में पूरी हो रही है और उसमें भी जब पेपर लीक का मामला आ जाए, तो निश्चित तौर पर पूरी युवा पीढ़ी और उनके परिवारों के बीच निराशा का माहौल पसर जाता है। जनता यह उम्मीद करती है कि उनके वोट से चुनी हुई सरकार उनके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद करें, लेकिन एक के बाद एक परीक्षाओं में देरी और उनके पेपर लीक होने के मामलों ने गहलोत सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा रखा है। पेपर लीक प्रकरण में शामिल लोगों पर कार्यवाही में देरी और उदारता भी वर्तमान सरकार के लिए महंगी पड़ी।

संगठन के स्तर पर देखें, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा फर्क है और वह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत सांस्कृतिक संगठन हैं, जबकि कांग्रेस के पास उस तरह के संगठनों का इतिहास जरूर है, लेकिन वर्तमान में वे संगठन लगभग निष्क्रिय हो चुके हैं। आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं से अधिक नेताओं की संख्या है। भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगी संगठनों में सबसे बड़ा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। इस तरह के सैंकड़ों संगठन हैं। उनके कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ न केवल अपने सांस्कृतिक-सामाजिक संगठन के लिए काम करते हैं, बल्कि समय आने पर वे भाजपा की मजबूत नींव की तरह खड़े रहते हैं और इससे भाजपा की राह आसान हो जाती है।

कांग्रेस में संगठन के स्तर पर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तनातनी ने भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। इसका नुकसान अंत तक हुआ क्योंकि टिकटों के वितरण के वक्त उम्मीदवार की योग्यता के बजाय उसके गुट को ज्यादा ध्यान में रखा गया। कई ऐसे उम्मीदवारों को भी टिकट दे दिया गया, जिनकी छवि आम लोगों के बीच में अच्छी नहीं है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी चुनाव प्रचार में जितनी मेहनत की, उससे उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिला।

इस चुनाव में राजस्थान में क्षेत्रीय दलों से जितनी उम्मीद थी, उतना बेहतर वे नहीं कर पाये, लेकिन फिर भी कुछ दलों की नयी उपस्थिति दिलचस्प जरूर है। सबसे दिलचस्प है भारत आदिवासी पार्टी। पहली बार चुनाव में उतरे इस दल ने तीन सीटों पर विजय प्राप्त करते हुए कांग्रेस और भाजपा के बाद तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में अपना नाम लिखवाया और आधा दर्जन सीटों पर दूसरे स्थान पर रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। चौरासी विधानसभा क्षेत्र से इस दल के उम्मीदवार राजकुमार रौत ने करीब सत्तर हजार वोटों से विजय प्राप्त कर संभवत: इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इस चुनाव का स्पष्ट संदेश है कि 2024 के आम चुनाव में अगर राजस्थान और उत्तर भारत में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है, तो भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों का निर्माण करना होगा और मजबूती से सभी मोर्चों पर जनता के बीच काम करना होगा, वरना उनके लिए 2024 की राह आसान नहीं होगी। यह कांग्रेस के लिए आत्मसमीक्षा का समय है।

5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का असर पड़ेगा राज्यसभा चुनावों पर

जयसिंह रावत

अभी-अभी सम्पन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का आगामी लोकसभा चुनावों पर असर पड़ेगा या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा; लेकिन इन चुनावों का 2024 में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों पर अवश्य ही असर पड़ेगा। खासकर मध्यप्रदेश में भारी जीत से भाजपा को राज्यसभा में अतिरिक्त ताकत मिलेगी। यही नहीं भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट हो रहे ''इंडिया गठबंधन'' पर इन चुनावों का असर दिखाई देगा।

इधर बदली हुई परिस्थितियां में बीआरएस को भी एनडीए के पक्ष में लाया जा सकता है। हालांकि राज्यसभा में अब बीआरएस की ताकत कम हो जाएगी। एनडीए की ताकत बढ़ने से आने वाले महीनों में राज्यसभा में कुछ विवादास्पद विधेयकों को पारित करने में आसानी होगी।

राज्यसभा में भाजपा की ताकत बढ़ेगी

संसद के उच्च सदन में अगले वर्ष अप्रैल में 65 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इसलिए 245 सदस्यीय राज्यसभा का द्विवार्षिक अगले साल की शुरुआत में ही इस सदन का चुनाव होना है जो कि सदस्यों के 6 साल का कार्यकाल पूरा होने पर होता है। राज्यसभा चुनाव में विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर ही विधायकों के मत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। इससे ही तय होगा कि किस पार्टी के कितने सदस्य चुने जाएंगे। जाहिर है जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी उस पार्टी के मत मूल्य अधिक होंगे और उसी पार्टी से राज्यसभा सदस्य चुना जाएगा।

इधर, पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों से अगले साल की शुरुआत में राज्यसभा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ताकत में और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र में फैली 19 सीटों पर राजनीतिक समीकरण अब बदल गए हैं। अब एनडीए, जिसके पास पहले से ही उच्च सदन में 123 का बहुमत है, उसकी संख्या में वृद्धि तय है। बढ़ी ताकत से उसे संवैधानिक संशोधन सहित कुछ महत्वपूर्ण कानून पारित करने में मदद मिलेगी।

केन्द्रीय मंत्रियों की राह हुई आसान

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एल मुरुगन (दोनों मध्य प्रदेश से), भूपेन्द्र यादव (राजस्थान), वी मुरलीधरन (महाराष्ट्र) और राजीव चन्द्रशेखर (कर्नाटक) अप्रैल 2024 में राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इनका इन विधानसभाओं में दोबारा चुनाव होना तय है। मध्य प्रदेश में पांच सीटें खाली होनी हैं। उपरोक्त दो मंत्रियों के अलावा, राजमणि पटेल और कैलाश सोनी (दोनों कांग्रेस) भी सेवानिवृत्त होंगे। एक सीट के लिए 46 विधायकों के वोटों की जरूरत है, ऐसे में कांग्रेस को इन दो सीटों में से केवल एक ही सीट मिलने की संभावना है। एक अन्य राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह (भाजपा) भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और भाजपा इस सीट को बरकरार रखेगी।

बीआरएस को एक झटका और लगेगा

उच्च सदन में बीआरएस को अब बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पार्टी के बीएल यादव, जे.संतोष कुमार और आर वद्दीराजू अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और अप्रैल में होने वाले चुनाव में पार्टी को केवल एक सीट मिलेगी। बाकी दो सीटों पर कांग्रेस को फायदा होगा। इसके अलावा, कर्नाटक से चार सीटें खाली होंगी जहां कांग्रेस ने इस साल मई में सरकार बनाई थी।

कांग्रेस से जीसी चन्द्रशेखर, एल हनुमंथैया, सैयद नासिर हुसैन और केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। राज्य में भाजपा के साथ मिलकर अलग हुई राकांपा और शिवसेना की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या में भी बदलाव हो सकता है। एनडीए को उच्च सदन में महाराष्ट्र से अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की संभावना है। 245 सदस्यों वाले सदन में जहां 123 बहुमत का आंकड़ा है, बीजेपी के पास 94 सदस्य हैं और उसे बीजेडी और वाईएसआरसीपी से मुद्दा-आधारित समर्थन मिलेगा।

अभी मध्य प्रदेश की 11 में से 8 सीटें भाजपा के पास

मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में इस बार भाजपा को 163 सीटें मिली हैं। जबकि साल 2018 के चुनाव में भाजपा को केवल 109 सीटें मिलीं थी। बाद में ज्योर्तिरादित्य सिंधिया के अपने साथी विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो जाने से भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया था और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, इसलिए भाजपा के 4 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने गए थे। जबकि एक सदस्य कांग्रेस की ओर से जीता था।

भाजपा की ओर से धर्मेंद्र प्रधान, कैलाश सोनी, अजय प्रताप सिंह और थावरचंद गेहलोत चुने गए थे। जबकि कांग्रेस की ओर से राजमणि पटेल चुने गए थे। अब इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को खत्म होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के कोटे में 11 राज्यसभा सीटें हैं. इसमें वर्तमान में बीजेपी के पाले में 8 सदस्य हैं जबकि कांग्रेस के पास केवल तीन सदस्य हैं. इसमें दिग्विजय सिंह, राजमणि पटेल और विवेक तन्खा शामिल हैं। इसमें राजमणि की सदस्यता 2 अप्रैल 2024 को खत्म हो जाएगी। जबकि दिग्विजय सिंह की सदस्यता 21 जून 2026 को खत्म हो रही है। इसके अलावा विवेक तन्खा की सदस्यता 29 जून 2028 तक है।

समीकरण बदलेंगे और विवादास्पद बिल आसानी से पास होंगे

विधानसभा चुनाव परिणाम अक्सर राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। कई राज्यों में किसी विशेष पार्टी का मजबूत प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति को मजबूत करता है। दरअसल, यह बढ़ी हुई ताकत उन्हें राज्य विधानसभाओं पर अपने प्रभाव के माध्यम से राज्यसभा में अधिक सीटें हासिल करने में मदद कर सकती है। यदि चुनाव परिणामों के कारण किसी भी राज्य में गठबंधन सरकार बनती है, तो इससे राजनीतिक दलों के बीच रणनीतिक गठबंधन या पुनर्गठन हो सकता है, जिससे राज्यसभा में उनकी सामूहिक ताकत पर असर पड़ सकता है।

सदस्यों की पर्याप्त संख्या राज्यसभा विधेयकों को पारित करने और विधायी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि राज्य चुनावों के कारण राज्यसभा की संरचना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होता है, तो यह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रमुख कानूनों के पारित होने या उसमें रुकावट को प्रभावित कर सकता है।

राज्य विधानसभा चुनावों के परिणामों के आधार पर पार्टियां अपने गठबंधनों और रणनीतियों पर पुनर्विचार कर सकती हैं। यह पुनर्मूल्यांकन उन गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है जो वे राज्यसभा चुनाव से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बनाते या तोड़ते हैं।

झूठ बोलने में इन 4 राशियों के लोग हैं पारंगत, बोलते हैं सफेद झूठ

मेषः मेष राशि के लोग झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन यदि स्थिति ऐसी है तो यह इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बता दें कि ये डेट जैसी छोटी-सी बात या चोट जैसी बड़ी बात के लिए झूठ बोल सकते हैं।

वृषभः वृषभ राशि के लोग आमतौर पर खुद को किसी समस्या की स्थिति में डालने का प्रयास नहीं करते। लेकिन, जब वे झूठ बोलते हैं तो वे सफेद झूठ बोलते हैं जो उनके लिए काम करता है।

मिथुनः यदि झूठ बोलना एक खेल होत तो मिथुन राशि वाले बिना प्रतिस्पर्धा के विजेता होते। वे इतनी जल्दी बातें बना सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कब झूठ बोला।

कर्क : कर्क राशि वाले जिससे प्यार करते हैं उसके लिए काफी प्रोटेक्टिव होते हैं। लेकिन परिवार, दोस्त या साथी ही ऐसे लोग हैं जिनके लिए यह झूठ बोलते हैं।

सिंहः इन्हें जोड़ना पसंद है। उनका झूठ सच के अतिशयोक्ति के रूप में जुड़ जाता है।

कन्याः अगर झूठ बोलने के बाद कन्या वालों का जीवन सरल हो जाए तो ये झूठ बोलेंगे। अगर झूठ बोलने से इनकी समस्या का समाधान होगा तो ये झूठ बोलेंगे।

तुलाः तुला राशि वालों का मानना है कि यह झूठ बोलने लायक है अगर यह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर इससे सभी को फायदा हो रहा है तो इसमें नुकसान क्या है।

वृश्चिकः वृश्चिक राशि वाले खुद को या किसी और को बचाने के लिए सबसे अच्छी तरह से झूठ बोलते हैं। यदि आपको कभी झूठ बोलने की आवश्यकता हो तो एक वृश्चिक राशि के व्यक्ति से झूठ बोलने के बारे में पूछें।

धनुः खुद को बचाने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। अगर वे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो बस पल भर अपराध बोध से सच उगलते देते हैं।

मकरः धनु राशि के समान ही मकर राशि वाले झूठ नहीं बोलेंगे। और अगर वे ऐसा करते हैं तो आपको बाद में इसके बारे में पता चल जाएगा।

कुंभः कुम्भ वालों के लिए झूठ बोलना एक कला की तरह है। हममें से अधिकांश लोग इनके मुंह से निकली हर बात पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि ये झूठ भी बड़े ही दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं।

मीनः यदि मीन राशि वाले झूठ बोल रहे हैं तो यह अच्छे के लिए है बोल रहे होते हैं। हालांकि, झूठ बोलने से पहले ये कई बार सोचते हैं।

मनी प्लांट ही नहीं, ये पौधे भी जगा सकते हैं आपकी सोई हुई किस्मत

वास्तु शास्त्र के में कई ऐसे पेड़-पौधे बताए गए हैं जिन्हें घर- में लगाने से परिवार की सुख-शांति बनी रहती है। यदि घर में पेड़-पौधे लगाते समय भी वास्तु का ध्यान रखा जाए तो, इससे व्यक्ति के सौभाग्य के रास्ते खुल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार लकी पौधे कौन-से हैं।

सकारात्मकता को बढ़ाती है तुलसी

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए सबसे पवित्र और शुभ पौधा तुलसी को माना गया है। धार्मिक महत्व के साथ-साथ तुलसी का पौधा वास्तु में भी विशेष महत्व रखता है। आप तुलसी को घर के आंगन, बालकनी या खिड़कियों के पास रख सकते हैं, जहां से इसे नियमित रूप से रोशनी मिल सके।

सौभाग्य का पौधा

बांस के पौधे को भी वास्तु और फेंगशुई दोनों में ही इसे सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। बांस के पौधे में 5, 6 या 7 डंठल लगाना शुभ माना जाता है। यह पौधा भी व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि करता है। बांस के पौधे को घर के पूर्व कोने में रखना चाहिए।

शमी का पेड़

भगवान शिव की पूजा में शमी का पौधा विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। ऐसे में शमी का पेड़ होने से भगवान शिव की कृपा साधक पर बनी रहती है। साथ पौधे को घर में लगाने से सौभाग्य आकर्षित होता है, जिसके प्रभाव से घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही इस पौधे को घर में लगाने से शनि के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है।

अपराजिता का पौधा

अपराजिता का पौधा का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसे में इस पौधे को घर की पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। माना जाता है कि इस पौधे को घर में लगाने से मां लक्ष्मी स्वयं घर में विराजमान रहती हैं, जिससे साधक को धन-धान्य की कोई कमी नहीं होती। साथ ही इस पौधे से परिवार को आरोग्य की प्राप्ति होती है।

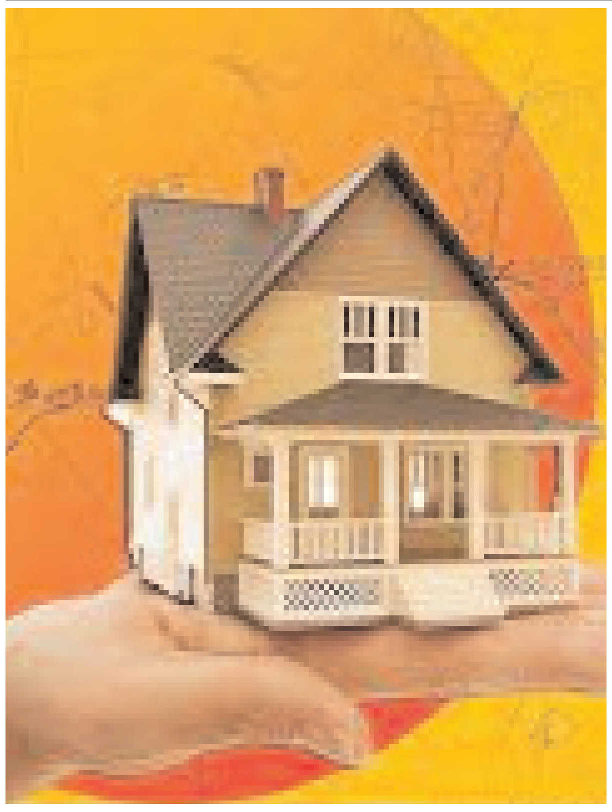

भूलकर भी इन 5 चीजों को न रखें खुला

सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। अनदेखी करने से घर की आर्थिक स्थिति बदहाल हो जाती है। वास्तु शास्त्र के जानकारों की मानें तो अनजाने में लोग कई चीजों को खुला छोड़ देते हैं। वास्तु में ऐसा करने की मनाही है। इन 5 चीजों को खुला रखने से वास्तु दोष लगता है। साथ ही कुंडली में चंद्र, बुध और शुक्र ग्रह कमजोर होते हैं। आइए जानते हैं-

नमक

ज्योतिषियों की मानें तो नमक का संबंध चंद्रमा से होता है। सोमवार के दिन नमक का दान करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। इस उपाय को करने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। साथ ही माता जी की सेहत भी अच्छी रहती है। हालांकि, नमक को कभी खोलकर या खुला न रखें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है।

किताब

वास्तु शास्त्र के अनुसार, किताब का संबंध बुध ग्रह से होता है। ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह मन, बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं। अतः किताबों को भी कभी खोलकर न रखें। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है। अतः कभी पढ़ने के दौरान किताब को खुला छोड़कर न रखें।

दूध

दूध और दही का दान करने से कुंडली में शुक्र और चन्द्रमा मजबूत होता है। अतः ज्योतिष सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध और दही दान करने की सलाह देते हैं। वहीं, दूध और दही को खुला छोड़ने से कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

खाना

वास्तु जानकारों की मानें तो भोजन को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इससे घर में अन्न और धन की कमी होने लगती है। वहीं, खुले में खाना रखने से दूषित (कीड़े-मकोड़े गिरने से) होने का भी खतरा रहता है।

अलमारी

अक्सर लोग जल्दबाजी में कपड़े या पैसे लेने या रखने के बाद अलमारी को खुला ही छोड़ देते हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसा करने की मनाही है। वास्तु शास्त्र के जानकारों की मानें तो अलमारी को खुला रखने से धन की देवी मां लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। इससे घर की सुख-समृद्धि धीरे-धीरे कम होने लगती है।

कहीं आपके घर में भी न हो जाए वास्तु दोष, इसलिए ज़रूर जानिए ये ख़ास वास्तु टिप्स

बिल्डर्स के लिए वास्तु का ध्यान रखते हुए घर बनाना मुश्किल है। अगर आप वास्तु में विश्वास करते हैं और नया घर खरीदने का सोच रहे हैं, तो अपने नए घर का वास्तु समझने के लिए इन वास्तु टिप्स का पालन करना चाहिए। वास्तु में घर के प्रत्येक हिस्से में पॉजिटिविटी और खुशी लाने लिए सही रंग, फॉर्मेट, आकार और दिशाओं का सुझाव दिया गया है। किसी मकान को घर बनाने के लिए उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए और वास्तु कहता है कि घर में रहने वाला व्यक्ति उस एनर्जी के प्रभाव में आता है।

नए घर का वास्तु टिप्स / घर का वास्तु- वास्तुशिल्प और आंतरिक क्षेत्र में एक गर्म विषय बनता जा रहा है, और इन युक्तियों का पालन करके, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका घर एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जगह है।

घर के लिए वास्तु - नए घर के लिए वास्तुवास्तु सिद्धांतों के अनुसार शांतिपूर्ण रहने का स्थान

ध्यान रखनी चाहिए ये बातें- कमरे का आकार नए घर का वास्तु में से एक है कमरों का आकार सही होना। घर का आकार वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए।

कमरे का वास्तु- घर के कमरे अच्छी रोशनी वाले, हवादार और साफ-सुथरे होने चाहिए।

फर्नीचर- घर के वास्तु के अनुसार, आपका भारी फर्नीचर जैसे बेड और अलमारी दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए। नए घर में सीढ़ियाँ दक्षिण-पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए।

वास्तु के अनुसार पानी- घर के लिए एक महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स है कि पौधे व पानी के माध्यम जैसे पानी की पेंटिंग, फव्वारा, मछलीघर आदि रखें।

डाइनिंग टेबल के लिए वास्तु टिप- आपके डाइनिंग स्पेस के लिए घर का एक महत्वपूर्ण वास्तु यह है कि यह मुख्य दरवाजे के पास नहीं होना चाहिए।

नए घर का वास्तु- घर का मुख्य द्वार न केवल मुख्य है, बल्कि ऊर्जा व जीवंतता का भी केंद्र है। आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसे इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि जब आप बाहर निकलें तो आपका मुख उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा की ओर हो। घर खरीदने या बनाने से पहले, सुनिश्चित करें कि घर इन विशेष दिशाओं पर केंद्रित हो।

घर के लिए वास्तु - गृह प्रवेश के लिए वास्तुघर का प्रवेश द्वार सही दिशा में होना चाहिए, प्रवेश द्वार डिज़ाइन करते समय ध्यान देने योग्य युक्तियाँ, प्रवेश द्वार के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली लकड़ी का उपयोग करें। मुख्य द्वार के बाहर कोई भी फव्वारा या पानी से संबंधित सजावट करने से बचें। प्रवेश द्वार के बाहर शू रैक या कूड़ेदान लगाने से बचें। मुख्य द्वार के पास बाथरूम बनाने से बचें। मुख्य द्वार को काले रंग से नहीं रंगना चाहिए। प्रवेश द्वार पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए। दरवाजे को नेमप्लेट और तोरण से सजाना चाहिए। दरवाज़ा दक्षिणावर्त दिशा में खुलना चाहिए। प्रवेश द्वार के पास किसी भी जानवर की मूर्ति न रखें।

बिस्तर के पास रखकर कभी न सोएं ये चीजें, वरना पैसों की कमी होते नहीं लगेगी देर

वास्तु शास्त्र में माना गया है कि यदि वस्तुओं को रखते समय वास्तु के नियमों का ध्यान न रखा जाए या फिर उन्हें गलत दिशा में रख दिया जाए, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन चीजों को सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए।

झाड़ू से संबंधित नियम

हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए इसे कभी भी गलत जगह पर नहीं रखना चाहिए, न ही रात को सोते समय बिस्तर के नीचे झाड़ू रखनी चाहिए। क्योंकि वास्तु अनुसार शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना गया।

इसके स्थान पर आप झाड़ू को ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहां इसपर किसी की नजर न पड़े। वही उत्तर-पश्चिम कोना भी झाड़ू रखने के लिए अच्छा माना गया है। वहीं, झाड़ू को कभी भी रसोई घर बेडरूम या पूजा कक्ष के पास नहीं रखना चाहिए। इससे व्यक्ति की समस्याएं बढ़ सकती हैं।

न रखें ये चीजें

साथ ही वास्तु शास्त्र में यह भी माना गया है कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल या घड़ी भी अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा अपनी पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी चीजें जैसे अखबार या किताब को अपने सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे विद्या का अपमान होता है।

रख सकते हैं ये चीजें

कपड़े में थोड़ी-सी फिटकरी बांधकर अपने तकिए के नीचे रखने से बुरे सपने आने की समस्या दूर हो जाती है। वही, रात को सोते समय डर के कारण अचानक से आंख खुल जाती है तो ऐसे में अपने तकिए के नीचे 5-6 छोटी इलाइची कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। रात में सोने से पहले अपने सिरहाने पानी के भरा पात्र भी रख सकते हैं।

जान लीजिए झाड़ू संबंधी वास्तु नियम, घर में कभी नहीं आएगी दरिद्रता

वास्तु शास्त्र में दिशाओं का महत्व है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर चीज का एक निश्चित जगह पर होने से घर में सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। इसी तरह वास्तु शास्त्र में झाड़ू संबंधी कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं जैसे झाड़ू कहां रखनी चाहिए या कब खरीदनी चाहिए।

झाड़ू रखने के नियम

झाड़ू रखने के लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच की जगह सबसे अच्छी मानी गई है। साथ ही कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इसकी जगह झाड़ू को हमेशा लिटाकर रखें। झाड़ू को रसोई घर में भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती है और कभी धन की कमी नहीं होती।

इन बातों का भी रखें ध्यान

ध्यान रखें की घर में कभी टूटी हुई झाड़ू नहीं होनी चाहिए। झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। साथ को गंदा करके भी नहीं रखना चाहिए। शाम के बाद कभी भी घर में झाड़ू न लगाएं। ऐसा करना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए खराब हो सकता है। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक झाड़ू लगाई जा सकती है।

कब खरीदें झाड़ू

नई झाड़ू खरीदने के लिए अमावस्या, मंगलवार, शनिवार और रविवार का दिन सबसे अच्छा माना गया है। वहीं, सोमवार और शुक्ल पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।

अपनाएं ये वास्तु उपाय, आने वाले साल में नहीं सताएगा कर्ज का डर

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की हर चीज को सही दिशा में रखा जाए तो इससे घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से भी बच सकता है। साथ ही वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे भी उपाय बताए गए हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को कर्ज से भी मुक्ति मिल सकती है।

वास्तु शास्त्र में माना गया है कि यदि वस्तुओं को रखते समय दिशा का ध्यान रखा जाए तो इससे व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। कई बार जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति न चाहते हुए भी कर्ज लेता है और चाहकर भी उस कर्ज से निकल नहीं पाता। ऐसे में व्यक्ति कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है और आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। ऐसे में आप कुछ वास्तु उपाय अपनाकर कर्ज रूपी राक्षस से मुक्ति पा सकते हैं।

इस दिशा में रखें तिजोरी

आप अपनी तिजोरी को सही दिशा में रखकर भी धन की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आप अपनी तिजोरी को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इससे व्यक्ति को धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और कर्ज से भी मुक्ति मिल सकती है।

ये दिन है शुभ

कर्ज चुकाने के लिए मंगलवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि माना जाता है कि मंगलवार के दिन पैसा लौटाने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज के राहत मिलती है। साथ ही घर या दुकान में उत्तर-पूर्व दिशा में दर्पण लगा कर भी कर्ज से राहत पाई जा सकती है।

जरूर करें ये काम

हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुबेर देव को धन का देवता माना गया है। वहीं, मां लक्ष्मी को भी धन की देवी माना जाता है। ऐसे में अपनी दुकान या ऑफिस की उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की मूर्ति या तस्वीर लगानी चाहिए। साथ ही रोजाना उनकी पूजा-अर्चना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिल सकता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

विधानसभा चुनाव में जीते 10 भाजपा सांसदों ने सांसदी छोड़ी

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद भाजपा ने भले ही मुख्यमंत्री को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन इन राज्यों में चुनाव लड़ कर जीतने वाले पार्टी के 10 सांसदों ने अपनी-अपनी सांसदी छोड़ दी है। जिन बड़े नामों ने अपनी संसद सदस्यता छोड़ी है, उनमें नरेंद्र तोमर से लेकर राज्यवर्धन राठौड़ तक के नाम शामिल हैं। जिन सांसदों ने सांसद पद छोड़ा है, उनमें मध्य प्रदेश से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रह्लाद पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक शामलि हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से अरुण साव और गोमती साई शामिल हैं। वहीं, राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दीया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा ने सांसद पद छोड़ा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद इन सांसदों के दल को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से मिलने पहुंचे। चुनाव जीतने वाले दो अन्य सांसद बाबा बालकनाथ और रेणुका सिंह इस दौरान नड्डा के साथ नहीं पहुंचे।

8 दिसंबर को 11 बजे राजभवन में शपथ लेंगे लालदुहोमा

आईजोल। जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के नेता लालदुहोमा शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज भवन के सूत्रों ने यह जानकारी दी। लालदुहोमा ने बुधवार को राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। सूत्रों ने कहा, ''लालदुहोमा शुक्रवार को सुबह 11 बजे राज भवन में होने वाले एक समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।'' जेडपीएम सोमवार को विधानसभा चुनाव में विजयी बनकर उभरी, उसने कुल 40 सीटों में से 27 पर जीत हासिल की। पार्टी के एक नेता ने कहा कि लालदुहोमा ने नवनिर्वाचित सदस्यों एवं अन्य नेताओं के साथ मंगलवार शाम को बैठक की और मंत्रिपरिषद के गठन एवं विभागों के बंटवारे पर चर्चा की। जेडपीएम ने राज्य विधानसभा चुनावों में निवर्तमान सत्तारूढ़ दल मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) को शिकस्त दी, जिसे केवल 10 सीटें मिलीं।

द्रमुक सांसद ने संसद में अपने विवादित बयान पर जताया खेद

नई दिल्ली। द्रमुक सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने अपनी एक विवादित टिप्पणी के लिए बुधवार को लोकसभा में खेद जताया और अपने बयान को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान कहा, मेरे द्वारा कल दिए गए बयान से सदस्यों और जनता के किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं उस बयान को वापस लेता हूं। मैं आग्रह करता हूं कि उसे कार्यवाही से हटाया जाए। मैं खेद जताता हूं। पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने कहा, बयान को पहले ही कार्यवाही से हटा दिया गया है और आपने खेद जता दिया है, मामला खत्म हो गया। सेंथिल कुमार ने मंगलवार को सदन में जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयकों पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए हिंदी भाषी राज्यों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी।

राहुल से सीख लेकर विपक्षी नेता टिप्पणी कर रहे : अनुराग

नईदिल्ली। द्रमुक सांसद डीएनवी सेंथिलकुमार एस. की गौमूत्र वाली टिप्पणी के मुद्दे पर बुधवार सुबह अपने आवास पर बुलाये गये संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना दिखाता है कि इन लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार यह किया। इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस को डीएमके के साथ रहना ज़रूरी है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ये (कांग्रेस) ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ते ही हैं लेकिन अब कारण उससे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अमेठी की हार के बाद से ही इसकी शुरुआत हो गई थी... उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाने का काम किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह चुनावों में अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करने के बजाय भारतीय संस्कृति और पहचान को अपमानित करने की साजिश रच रही है।

दिल्ली जल बोर्ड का कैग से ऑडिट कराने का निर्देश दिया

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के रिकॉर्ड का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने का आदेश दिया है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 15 साल के रिकॉर्ड का ऑडिट कराया जाएगा। एक सूत्र ने कहा, ''दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीजेबी का ऑडिट कराने का निर्देश दिया है।'' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और 'आप' के बीच दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले महीने से खींचतान चल रही है। केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि विपक्ष कुछ आरोप लगा रहा है। तो, इससे (ऑडिट) सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हमने दिल्ली जल बोर्ड के पिछले 15 वर्षों के सीएजी ऑडिट का आदेश दिया है...अगर किसी ने कुछ गलत किया है, तो उन्हें दंडित किया जाएगा।

इंडिया गठबंधन में बढ़ सकती है दरार! मजबूत प्रत्याशी होने पर ही सहयोगी दलों को सीटें देगी सपा

कांग्रेस की बात मानने को तैयार नहीं क्षेत्रीय दल

लखनऊ। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे की कवायद शुरू होनी है, पर मौजूदा परिस्थितियों में यह गुत्थी आसानी से सुलझते हुए नहीं दिख रही है। सपा ने फैसला किया है कि घटक दलों के पास मजबूत प्रत्याशी होने पर ही वह कोई भी सीट छोड़ेगी। सीटों के बंटवारे के लिए तृणमूल, सपा और डीएमके सरीखी क्षेत्रीय पार्टियां भी एकसमान फॉर्मूला अपनाने पर सहमत हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 6 दिसंबर को इंडिया के प्रमुख 15 घटक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डीएमके नेता एमके स्टालिन, जदयू नेता नीतीश कुमार और झामुमो के नेता हेमंत सोरेन ने बैठक में भाग लेने से मना कर दिया। इसके बाद बुधवार को होने वाली बैठक को टाल दिया गया है। इंडिया के सूत्रों का कहना है कि अब क्षेत्रीय शक्तियां भी सीटों के लिहाज से कांग्रेस की बहुत ज्यादा बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सपा पहले ही कांग्रेस से कह चुकी है कि यूपी में वो जो सीटें चाहती है, उन पर किस नेता को लड़ाएगी, पहले यह बताए। सपा के रणनीतिकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी तभी लड़ाई में आता है, जब उसके पास कम से कम डेढ़ से दो लाख बुनियादी वोटों का इंतजाम हो। तब गठबंधन के कारण जुड़ने वाला वोट उसे जीत की ओर ले जाता है। इसलिए पहले कांग्रेस को यह बताना होगा कि डेढ़ से दो लाख बुनियादी वोट हासिल कर सकने वाले कौन से नेता उसके पास हैं। सीट बंटवारे की बात उसके बाद ही शुरू होगी। सपा सूत्रों का कहना है कि इंडिया की समन्वय बैठक में मांगे जाने के बावजूद कांग्रेस ने उन नेताओं की सूची नहीं सौंपी है, जिन्हें वह यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है।

पीएम के लिए राउत ने आगे किया उद्धव का नाम

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने बुधवार को अपनी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे का नाम तब लिया जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या 2024 के आम चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक के पास प्रधान मंत्री पद का चेहरा होना चाहिए। हालाँकि, उन्होंने सीधे तौर पर ठाकरे का नाम दौड़ में डालने से बचते करते हुए कहा कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहते जिससे पार्टियों के बीच दरार पैदा हो।

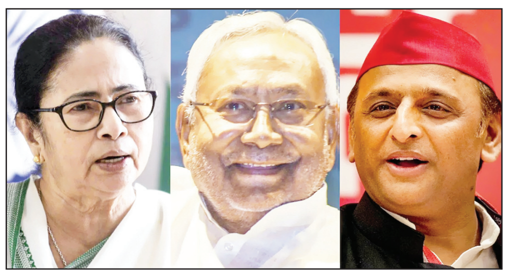

इंडिया को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होगी। वास्तव में एक चेहरा होना चाहिए। उद्धव ठाकरे एक हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी चेहरा हैं। जिस व्यक्ति को इंडिया गठबंधन के सदस्यों की मंजूरी मिलेगी, वह (पीएम) चेहरा हो सकता है। मैं बाहर कुछ भी नहीं कहना चाहता जिससे गठबंधन में कोई दरार पैदा हो।

राउत ने आगे कहा कि आज शाम को बैठक होने वाली थी... ममता जी के घर में कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि स्टालिन जी राज्य में बाढ़ की स्थिति को लेकर काम कर रहे हैं और बाकी के नेताओं के भी कुछ कार्यक्रम है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने तय किया कि हम 16 या 18 दिसंबर को बैठक करेंगे। आपको बता दें कि तीन हिंदीभाषी राज्यों में हालिया विधानसभा चुनाव हारने के बाद कई इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने भाजपा विरोधी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने के कांग्रेस पार्टी के अधिकार पर सवाल उठाया है। गठबंधन में दरार तब और स्पष्ट हो गई है जब कई घटक दलों ने आज इसकी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसे कांग्रेस पार्टी ने चुनावी हार के बाद बुलाया था। छह दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित बैठक के 'रद्द होने' को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लालू प्रसाद ने यह जानकारी दी। कयास लगाए जा रहे थे 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में कई नेताओं ने शामिल होने को लेकर अनिच्छा जताई थी। कांग्रेस के सहयोगी और नेहरू-गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले लालू प्रसाद ने कहा, ''बैठक अब 17 दिसंबर के लिए पुनर्निर्धारित की गई है।'' अटकलें लगाई जा रही थीं कि लालू प्रसाद के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को बैठक में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे।

हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग काम करे : नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते है कि इंडी गठबंधन का काम आगे बढ़े। बहुत तेजी से जल्दी से जल्दी सब बात हो जाए। हम तो बीमार थे। हमको बुखार हो गया था, इसलिए मीटिंग में नहीं जा पाए। बाद में जब आगे भी मीटिंग होता तो हम नहीं जाएंगे क्या? ऐसा संभव है? हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग काम करे। अगला मीटिंग में हम फिर कहेंगे सब से कि बहुत तेजी से आपस में थोड़ा बात करके आपस में सबकुछ तय कर लीजिए। अब देर मत कीजिए। आप देख रहे हैं कि हम एक साल से कितना कोशिश कर रहे हैं। बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पार्टी लड़ने लगता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे बारे में बिना मतलब के कहा जाता है कि हम चाहते हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर लड़ें। हम देश हित में चाहते हैं। जो लोग अभी पावर में हैं, पूरा का पूरा इतिहास बदल रहे हैं। हम तो चाहते हैं सब एकजुट हों और जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं। हम इतना दिन तक सेवा नहीं किए क्या? हम चाहते हैं सबलोग एकजुट होकर लड़ें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमको हल्का सा बुखार हो गया था। तापमान 100 भी नहीं पहुंचा था। सर्दी और खांसी था इसलिए आराम कर रहे थे। हम तो राज्य के हित में काम कर रहे हैं। देश के हित में सबलोग (इंडी गठबंधन) एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जातीय आधारित गणना पर कहा कि हमने जाति और आर्थिक सर्वे करवाया। पता चला कि अपर कास्ट समेत हर कास्ट में गरीबी है। हमने गरीब परिवार को दो-दो लाख तक का सहायता दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जाति गणना और आर्थिक सर्वे कराती तो देश को कितना फायदा होता है। पूर्वीय क्षेत्रीय विकास परिषद बैठक के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि उसमें तो हम सबलोग रहेंगे। वह तो परंपरा है, उसमें तो सभी लोग रहेंगे। 10 दिसंबर को बैठक है, सभी लोग रहेंगे। बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं।

कांग्रेस को लेकर कर दी थी पूर्व राष्ट्रपति ने बड़ी भविष्यवाणी

जब राहुल ने फाड़ा था अध्यादेश गुस्से से लाल हुए थे प्रणब मुखर्जी

नईदिल्ली। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा द्वारा लिखी गई एक नई किताब, प्रणब, माई फादर: ए डॉटर रिमेम्बर्स (रूपा पब्लिकेशंस इंडिया), पूर्व राष्ट्रपति और आजीवन कांग्रेसी की डायरी प्रविष्टियों पर आधारित है, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी पर तीखे हमले किए गए हैं। मुखर्जी की व्यक्तिगत नोटबुक में उनके निधन से ठीक एक महीने पहले 28 जुलाई, 2020 को एक आलेख में कहा गया है कि गांधी-नेहरू परिवार के लिए संरक्षित खेल का मैदान बनाकर कांग्रेस ने अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो दिया, जिसका असर देश की राजनीति पर पड़ा। आजादी के बाद अगर एक ही परिवार के 5 सदस्यों का कांग्रेस अध्यक्ष पद पर 37 साल तक कब्जा रहा, तो यह आधिपत्य के सबसे खराब रूप की बात करता है।

उसमें यह भी कहा गया था कि परिवार आज संगठन को शक्ति प्रदान नहीं कर रहा है जिससे उसकी ताकत खतम हो रही है। 2004 के बाद से सोनिया गांधी और राहुल ने 2001-2003 में सोनिया जी द्वारा अर्जित आधार को आंशिक रूप से भी खो दिया है। उनकी रुचि तो बस इसी में है कि किसी तरह अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई जाए। सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड की गई और वस्तुनिष्ठ रूप से लिखी गई, मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने बड़ी मेहनत से इसे तैयार किया है, जो यूपीए के घटनापूर्ण वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला पर से पर्दा और रहस्य उठाती है।

मुखर्जी को 1960 के दशक की शुरुआत से ही सावधानीपूर्वक डायरी लिखने की आदत विकसित हो गई थी। शर्मिष्ठा, जिनका एक संक्षिप्त कार्यकाल एक राजनेता के रूप में था, के अनुसार, यह पुस्तक डायरी प्रविष्टियों और वर्षों में विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ उनकी बातचीत पर आधारित है। मुखर्जी विशेष रूप से राहुल की आलोचना करते हुए उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता और अनुप्रयोग की कमी का

दस्तावेजीकरण करते हैं। 2013 में जब राहुल ने उस अध्यादेश को खारिज कर दिया था, जिसमें दोषी राजनेताओं को बचाने की मांग की गई थी, तब तक मुखर्जी राष्ट्रपति भवन चले गए थे। उस रात, मुखर्जी ने अपनी डायरी में लिखा, राहुल गांधी ने अजय माकन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया और कैबिनेट के फैसले को 'बकवास' बताया। यह पूरी तरह से अनावश्यक है। उनके पास राजनीतिक कौशल के बिना अपने गांधी-नेहरू वंश का सारा अहंकार है।

मुखर्जी ने बताया कि कैसे उनके कार्यालय को कपिल सिब्बल और अहमद पटेल से फोन आए थे, जिसमें उनसे अध्यादेश पर कोई कार्रवाई न करने का अनुरोध किया गया था। हालाँकि, मुखर्जी ने आश्चर्य जताया कि राहुल के कार्यों का गठबंधन सहयोगियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शर्मिष्ठा का कहना है कि उन्होंने ही सबसे पहले उन्हें यह खबर दी थी। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने पिता को इतना क्रोधित होते देखा! उनका चेहरा लाल हो गया और चिल्लाकर बोले, वह (राहुल) खुद को कौन समझता है? वह कैबिनेट के सदस्य नहीं हैं। कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक रूप से खारिज करने वाला वह कौन होता है? प्रधानमंत्री विदेश में हैं। क्या उन्हें इस बात का भी एहसास है कि उनके कदमों का असर प्रधानमंत्री और सरकार पर पड़ेगा? उन्हें प्रधानमंत्री को इस तरह अपमानित करने का क्या अधिकार है? शर्मिष्ठा के अनुसार, मुखर्जी ने राहुल के फैसले को कांग्रेस के लिए ताबूत में आखिरी कील के रूप में देखा।

खेल
प्रमुख समाचार

भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए रवाना

नईदिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ञ्20 सीरीज में 4-1 से मिली शानदार जीत के बाद भारतीय टीम अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दौरे के लिए पूरी तरह से तैयार है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम तीन टी20, तीन वनडे और दो टेस्ट मुकाबले खेलेगी। टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था। भारतीय टीम के तरफ से रिंकू सिंह ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। रिंकू सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में अपना कौशल दिखाया और 5 मैचों में 52.50 की शानदार औसत और 175.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 105 रन बनाए।

भारतीय टीम 10 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किंग्समीड स्टेडियम में अपनी सीरीज की शुरुआत कर रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत टी20 मैच के साथ सीरीज की शुरुआत करेगी। दूसरा टी20 मैच 12 दिसंबर को सेंट जॉर्ज ओवल में खेला जाएगा। तीसरा और अंतिम टी20 मैच 14 दिसंबर को वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। जिसके बाद वनडे सीरीज 17 दिसंबर से खेला जाएगा। पहला मुकाबला वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। जिसके बाद दूसरा और तीसरा मुकाबला 19 दिसंबर और 21 दिसंबर को खेला जाएगा। वनडे मुकाबले के बाद, भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में 26 दिसंबर से टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से केपटाउन में खेला जाएगा।

भारतीय टीम के घातक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, दक्षिण अफ्रीका के रास्ते में। तस्वीर में रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा और कुलदीप यादव के साथ नजर आए। सभी खिलाड़ी के चहरे पर सीरीज को लेकर उत्साह नजर आ रहा है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 358 अंक चढ़ा निफ्टी 20900 के पार

नईदिल्ली। अदाणी ग्रुप, एफएमसीजी, आईटी और पीएसयू बैंकों के शेयरों में तेजी के बीच आज घरेलू शेयर बाजार नई ऊंचाई पर पहुंच गए। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 358 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 83 अंक की बढ़त दर्ज की गई। व्यापक बाजारों में, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक क्रमश: 0.19 प्रतिशत और 0.18 प्रतिशत बढ़कर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 357.59 अंक यानी 0.52 फीसदी की बढ़त के साथ 69,653.73 अंक के नए शिखर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 69,744.62 और 69,395.01 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 82.60 अंक यानी 0.4 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 20,937.70 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 20,961.95 और 20,852.15 के रेंज में कारोबार हुआ।

रॉकेट बना अदाणी ग्रुप का अदाणी टोटल गैस का शेयर

नईदिल्ली। अदाणी टोटल गैस के शेयरों में बुधवार को भी तेजी जारी रही। आज इंट्राडे ट्रेड में कंपनी का शेयर बीएसई पर 20 प्रतिशत बढ़कर 1,053.80 रुपये पर पहुंच गया। निवेशकों के बीच इस शेयर को लेकर काफी उत्साह है। इस बात का अंदाजा सिर्फ इससे लगाया जा सकता है कि इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में तीन गुना से अधिक का उछाल देखा गया। दोपहर 2.40 बजे तक एनएसई और बीएसई पर कुल मिलाकर 2.7 करोड़ इक्विटी शेयरों का लेनदेन हुआ है। पिछले तीन कारोबारी दिनों में गौतम अदाणी के नेतृत्व वाली इस कंपनी का शेयर 50 प्रतिशत बढ़ गया है। 24 नवंबर से, यानी आठ कारोबारी सत्रों में, कंपनी द्वारा अहमदाबाद में ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण पायलट परियोजना शुरू करने के बाद, अदाणी टोटल गैस का शेयर 530.75 रुपये के स्तर से 99 प्रतिशत बढ़ गया है।

भारत में इथेनॉल का प्रोडक्शन 12 प्रतिशत बढ़ा

नईदिल्ली। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि देश में इस साल इथेनॉल का उत्पादन बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है और भारत 2025 तक इथेनॉल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गये एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच के कारण इस साल इथेनॉल का उत्पादन बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है और इस कारण कई बंद पड़ी चीनी मिलें शुरू हो गई हैं और लाभ में आ गयी हैं। उन्होंने कहा, ''इससे नई नौकरियों का सृजन हो रहा है और गन्ना किसानों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। सहकारिता क्षेत्र में भी जो चीनी मिलें बंद थीं, वे भी शुरू हो गई हैं।'' गोयल ने कहा कि चीनी मिलों में अब चीनी के उत्पादन के साथ इथेनॉल का संयंत्र लगने से देश की सभी चीनी मिलें लाभ में हैं और एक तरह से 'सर्कुलर' अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही है।

इस बार कोयले का उत्पादन 1 अरब टन होने का अनुमान

नईदिल्ली। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को अवगत कराया कि देश में कोयले का उत्पादन करीब एक अरब टन होने की संभावना है और आने वाले समय में सरकार कोयले का आयात बंद करने वाली है। सरकार ने यह भी कहा कि देश में वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू हो गया है और इस साल ऐसी खदानों से डेढ़ करोड़ टन कोयला उत्पादन होगा। कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गये अलग-अलग पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये बातें कहीं। जोशी ने कहा कि पहले देश में 54 करोड़ टन से लेकर 56.50 करोड़ टन तक कोयले का उत्पादन होता था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा एक अरब टन का होने वाला है और भारत कोयला उत्पादन के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि आने वाले समय में इसका आयात बंद कर दिया जाएगा।

राज्यों में कोई जीते, विदेशी निवेशकों को फर्क नहीं पड़ता

स्वामिनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर

मैं एक टेलिविजन प्रोग्राम में था। वहां मुझसे यह सवाल भी पूछा गया कि राज्यों में हुए चुनाव का विदेशी निवेशकों पर क्या असर होगा? उस प्रोग्राम में कुछ ऐसे जानकार थे, जिन्होंने कहा कि इसका पॉजिटिव असर होगा। वे मेरे जवाब से जरूर मायूस हुए होंगे।

मैंने उस प्रोग्राम में कहा कि राज्यों के चुनाव से विदेशी निवेशकों को फर्क नहीं पड़ता। वे जानते हैं कि राज्यों में होने वाले चुनाव में उतार-चढ़ाव होते हैं। कभी एक जीतता है तो कभी दूसरा। विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी इसमें होती है कि केंद्र में किसकी सरकार है। वे मानकर चल रहे हैं कि 2024 में फिर से मोदी प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। भले बीजेपी को पिछली बार से कुछ कम सीटें मिलें या कुछ ज्यादा। यही देखकर वे अभी भारत में निवेश के फैसले ले रहे हैं। इसलिए पांच राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों का भारत में विदेशी निवेश पर असर नहीं होगा।

विदेशी निवेशकों के लिए अच्छी बात यह भी है कि अमेरिका में आर्थिक विकास दर (जीडीपी ग्रोथ) अच्छी है, जबकि वहां कर्ज काफी महंगा हुआ है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (जैसे भारत में रिजर्व बैंक है) ने महंगाई दर पर अंकुश लगाने के लिए आक्रामक ढंग से कर्ज महंगा किया है। पहले जब वह ऐसा करता था तो वहां मंदी आ जाती थी। इसलिए निवेशकों को लग रहा था कि इस साल अमेरिका में मंदी आएगी। असल में फेडरल रिजर्व ने कहीं लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची बनाए रखीं। जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इससे महंगाई दर कम होकर 3.2 फीसदी पर आ गई, जो पहले से आधी है। लेकिन यह 2 फीसदी के लक्ष्य से अभी भी अधिक है।

वहीं, जुलाई से सितंबर के बीच अमेरिका की आर्थिक विकास दर 5.2 फीसदी रही। पूरे साल में यह 4 फीसदी रह सकती है। यानी अमेरिकी ग्रोथ शानदार बनी हुई है।

यूरोप में भी देखिए तो जर्मनी में जुलाई से सितंबर के बीच ग्रोथ माइनस 0.1 फीसदी रही। माना जा रहा था कि इसमें कहीं ज्यादा गिरावट आएगी। चीन में इस साल ग्रोथ 5.4 फीसदी रह सकती है। ये आंकड़े मैं यह समझाने के लिए दे रहा हूं कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था अनुमान से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यह सिलसिला 2024 में भी जारी रहेगा।

इसलिए दुनिया भर के शेयर बाजारों में आगे भी तेजी बनी रह सकती है। ऐसे में उभरते हुए बाजारों से पहले जो पैसा विदेशी निवेशकों ने निकाला था, वह वापस आएगा। इस मामले में भारत का प्रदर्शन लंबे समय में अच्छा रह सकता है क्योंकि चीन की ग्रोथ पहले की तुलना में घट रही है। इसलिए मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों का मार्केट पर असर नहीं होगा।

फर्ज कीजिए कि कांग्रेस मध्य भारत के दो या तीन राज्यों में चुनाव जीत जाती तो क्या विदेशी निवेशकों पर इसका असर होता? मुझे ऐसा नहीं लगता। विदेशी जानकारों को पता है कि मोदी, बीजेपी या मुख्यमंत्रियों से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हैं। पहले यह देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मत प्रतिशत राज्यों में होने वाले चुनावों की तुलना में 5 से 10 फीसदी तक अधिक होता है।

इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं दिल्ली की मिसाल दूंगा। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली की सभी सातों संसदीय सीटों पर जीत मिली। लेकिन इसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो 70 में से 3 सीटें ही उसके खाते में आईं। बाकी आम आदमी पार्टी को मिलीं। 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सारी सीटें जीतीं और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में उसे 70 में से 8 सीटें ही मिलीं। यानी केंद्र और राज्य के चुनाव का ट्रेंड अलग होता है।

सच यही है कि मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से अर्थव्यवस्था को संभाला है, विदेशी निवेशक उससे खुश हैं। वैसे, कांग्रेस के प्रवक्ता दोहराते रहेंगे कि 2004-2014 के बीच जब यूपीए का राज था, तब जीडीपी ग्रोथ मोदी राज के 10 वर्षों की तुलना में अधिक थी।

संसद में की गई साधना का लाभ छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में समर्पित- अरुण साव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सौंपा सांसद पद से इस्तीफा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से अनुमति लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद अरुण साव एवं रायगढ़ से सांसद श्रीमती गोमती साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए सांसद पद से अपना इस्तीफा सौंपा।

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य की लोरमी सीट से प्रचंड मतो से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि सांसद रहते हुए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में उन्होंने लोकतंत्र की गहराइयों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और देश के गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में जो सीखा है, वह छत्तीसगढ़ राज्य की जनता की सेवा और राज्य के सुशासन पूर्ण विकास के लिए अत्यंत सहयोगी साबित होगा।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय लोकतंत्र की पाठशाला है। हमें सिखाया गया कि राष्ट्र प्रथम के अटल सिद्धांत पर चलते हुए देश के विकास तथा जनता की बेहतरी के लिए उत्कृष्ट कार्य कैसे किया जाता है। भाजपा ने मुझे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने के बाद छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में योगदान का दायित्व सौंपा है।

श्रीमती गोमती साय ने कहा मैंने पार्टी के निर्देश पर विधानसभा चुनावों में पत्थलगांव से प्रत्याशी के रूप चुनाव लड़ा और जीतकर अब छत्तीसगढ़ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करूंगी।

मंत्रियों का चयन बड़ी चुनौती,प्रोटेम स्पीकर होंगे बृजमोहन अग्रवाल

जातिवाद, क्षेत्रीयता और अनुभव का रखा जाएगा ध्यान

रायपुर। मुख्यमंत्री तो ठीक है दिल्ली से तय हो जायेगा,प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिल्ली से कल परसों में पर्यवेक्षक पहुंच जायेंगे। विधायक दल की बैठक औपचारिक राजशुमारी के लिए होगी। इसके बाद पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल के गठन को लेकर होगी । बताया तो जा रहा है कि इसको लेकर राष्ट्रीय और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के बीच मंथन का दौर चल रहा है । इस बीच एक बात तो तय है कि प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के आठ बार के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल होंगे ।

भाजपा के 8 पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, केदार कश्यप, लता उसेंडी, पुन्नू लाल मोहिले और विक्रम उसेंडी अच्छी लीड से जीतकर आए हैं । इसी तरह तीन सांसद अरुण साव, रेणुका सिंह और गोमती साय भी विधायक चुने गए हैं । इसी क्रम में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णु देव साय और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक जीते हैं । मंत्री के लिए इन सभी की दावेदारी है । इसके अलावा ओपी चौधरी, विजय शर्मा जैसे 28 नए चेहरे भी जीते हैं । इसमें से मंत्री का चयन करना बड़ा चुनौती है। ऐसी चर्चा है कि मंत्रिमंडल के चयन में जातिवाद, क्षेत्रीयता और अनुभव का ध्यान रखा जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित विधायकों में से 17 के खिलाफ आपराधिक मामले

छह के खिलाफ गंभीर मामले

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं. इसके साथ ही नवनिर्वाचित विधायकों का बही-खाता भी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने पेश कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, नवनिर्वाचित 90 विधायकों में से 17 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं. हालांकि, यह 2018 में निर्वाचित होकर आए 24 दागी विधायकों से कम है. एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में किए गए विश्लेषण में 90 विधेयकों में से 17 (19प्र) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. 2018 में 24 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले और 13 विधायकों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे.

रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के 54 विधायकों में से 12 और कांग्रेस के 35 विधायकों में से 5 ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि, भाजपा के 54 विजयी उम्मीदवारों में से 4 और कांग्रेस के 35 विजयी उम्मीदवारों में से दो ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है.

70 विधायक करोड़पति- एडीआर रिपोर्ट में विधायकों के आपराधिक पृष्ठभूमि के अलावा संपत्तियों की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ के 90 नवनिर्वाचित विधायकों में से 72 करोड़पति हैं, जबकि 2018 में 68 विधायक करोड़पति थे. वर्तमान में 72 करोड़पति विधायकों में से भाजपा के 43 और कांग्रेस के 29 विधायक करोड़पति हैं.

भाजपा के विधायक ज्यादा अमीर- यही नहीं नवनिर्वाचित विधायकों की औसत संपत्ति 5.25 करोड़ रुपए है, जबकि 2018 में प्रति विधायक औसत संपत्ति 11.63 करोड़ रुपए थी. भाजपा के 54 विधायकों की औसत संपत्ति 5.70 करोड़ रुपए है, जबकि कांग्रेस के 35 विजेता उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 4.70 करोड़ रुपए है. वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एकमात्र विधायक की औसत संपत्ति 26.03 लाख रुपए है.

संजय नगर व सुंदर नगर में निगम ने हटाए अवैध ठेले व दुकानें

रायपुर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे से मंगलवार को मिले निर्देश के बाद नगर निगम का निगम पूरे दलबल के साथ पूरे रायपुर शहर में अवैध कब्जा हटाने के लिए निकल गया है। इसी कड़ी में बुधवार को नगर निगम का अमला सुबह-सुबह संजय नगर पहुंचा और डामर सड़क के आधे हिस्से पर नीव डालकर बनाई गई 12 दुकानों को धराशायी कर दिया। उल्लेखनीय हैं कि यहां पर 3 साल पहले रिंग रोड से लगाए बकरा मार्केट के पीछे सड़क को आधा कर आधे सड़क पर दुकानें बना ली गयी थी और अवैध रुप से ये 12 दुकानदार अपना व्यवसाय कर रहे थे।

ठीक इसी प्रकार जोन क्रमांक 5 का अमला सुबह 11 बजे लाखे नगर चौक से लेकर सुंदरनगर चौक तक अवैध कब्जा कर ठेले व गुमटी लगाकर व्यवहार कर रहे दुकानदारों के सामानों को जप्त किया। नगर निगम के अधिकारियों ने इन सभी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर दोबारा यहां पर दुकानें व ठेलों का संचालन किया जाता है तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।

इसी तरह जब्बार नाला वीआईपी तिराहा के पास अवैध रूप से बनी दुकानों को भी जमींदोज किया गया। इस दौरान नगर निगम का अमला भारी पुलिस बल के साथ मौजूद था ताकि निगम का दस्ता इन अवैध कब्जाधारी दुकानों को आसानी से तोड़ सकें।

मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, संविदा सचिव डीडी सिंह को हटाने की मांग को लेकर जमकर किया प्रदर्शन

रायपुर। प्रदेश में सरकार बदलते ही पिछली सरकार के अधिकारियों और वर्षो से मंत्रालय में जमे अधिकारियों के विरुद्ध स्वर मुखर होने लगे हैं. इसी कड़ी में आज मंत्रालय में कर्मचारियों की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह के विरुद्ध जबरदस्त प्रदर्शन और नारेबाजी की स्थिति उत्पन्न हुई है. ऋङ्कस्न स्नद्बद्दद्ध ङ्क प्यार, धोखा और अंजाम = प्रेमिका को मारा चाकू, फिर पानी टंकी पर चढ़कर आशिक ने मचाया हंगामा और जहर का किया सेवन, जानिए पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह मंत्रालय में मंत्रालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की ओर से सचिव से मिलकर मंत्रालय में लम्बे समय से लंबित डीपीसी करवाने और विगत दो वर्षों से अटके पड़े सेटअप रिवीजन के संबंध में अपनी बात रखी गई. पदाधिकारियों के अनुसार, सचिव की ओर से नियमों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से डीपीसी को अगले साल के लिए टालने के साथ ही सेटअप रिवीजन की नस्ती को भी अगले वित्तीय वर्ष में सोचने की बात कही गई. संघ पदाधिकारियों की ओर से उस स्थिति से कर्मचारियों को अवगत कराया गया, जिससे कर्मचारी/अधिकारी आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में संघ पदाधिकारियों सहित डीडी सिंह के कक्ष के सामने बैठ गए. कर्मचारियों ने डीडी सिंह की संविदा समाप्त करने के साथ ही मंत्रालय में संविदा समाप्त करने के नारे भी लगाए.

मामला बिगड़ता देख मुख्य सुरक्षा अधिकारी और सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य अधिकारियों ने बीच बचाव किया और सभी उपस्थित कर्मचारियों के समक्ष पदाधिकारियों की बैठक सचिव के साथ हुई. इसमें सचिव ने नियमानुसार तत्काल डीपीसी की बैठक आयोजित करने पर सहमति के बाद कर्मचारी वापस जाने पर राज़ी हुए.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों के अंदर काफी समय से आक्रोश था, जो आज मंत्रालय में इस रूप में परिलक्षित हुआ. पिछली सरकार के उपकृत मंत्रालय में ऐसे और भी कुछ अधिकारी हैं, जिनके ऊपर आने वाले दिनों में कर्मचारियों का गुस्सा फूटने की संभावना बताई जा रही है.

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

विधानसभा का विघटन, पूर्व विधायक खाली करेंगे आवास, अकबर ने खाली किया बंगला

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पंचम विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कार्यकाल की समाप्ति के बाद साल 2018 में हुए चुनाव में निर्वाचित हुए सभी विधायकों की विधायकी खत्म हो गई है। वहीं इन विधायकों में से जो इस बार चुनाव नहीं जीत पाए है, या फिर जिन्हें टिकट नहीं मिली है ऐसे विधायक अब पूर्व विधायक की श्रेणी में आ गए है। कार्यकाल खत्म होने के साथ ही उन्हें दी जा रही सभी शासकीय सुविधाएं भी समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय ने हारने वाले और जो चुनाव नहीं लाडे है ऐसे सभी विधायकों को विधायक आवास खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। सिविल लाइन स्थिति मंत्रियों के आवास भी खाली होने शुरू हो गए हैं। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर ने सबसे पहले अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। हालांकि कुछ पूर्व मंत्री अभी बंगाला खाली करने के मूड में नहीं है, इस वजह से उन्होंने बंगले के बाहर पूर्व मंत्री लिखा दिया है। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद वे राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।

कोयला घोटाला मामले में हुई सुनवाई

विधायक देवेंद्र समेत 9 लोग कोर्ट में नहीं हुए हाजिर, जज ने जेलर को लगाई फटकार

रायपुर. छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला मामले में रायपुर कोर्ट में आज सुनवाई हुई. कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत 9 लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तीसरी बार कोर्ट ने देवेंद्र यादव समेत 9 लोगों को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी किया था पर कोई नहीं आए. कोयला घोटाला मामले की सुनवाई सुनवाई विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में हुई. जेल में बंद आरोपियों के जेल से कोर्ट नहीं आने पर ईडी के वकील ने आपत्ति जताई. आपत्ति के बाद जेलर को कोर्ट में तलब कर जज ने फटकार लगाई. आनन-फानन में जेल प्रशासन ने लंच के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 6 जनवरी तय की है.

सदन में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार से बेदखल होने के बाद कांग्रेस में अब नेता प्रतिपक्ष के लिए माथा पच्ची हो रही है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में ये बड़ा सवाल है कि आखिर कौन छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस जिम्मेदारी को निभाएगा। इधर नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में कांग्रेस के कई नाम सामने आ रहे हैं। स लिस्ट में सबसे ऊपर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चरणदास महंत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री उमेश पटेल के नाम की भी चर्चा है। खबर ये भी है कि भाजपा द्वारा सरकार के मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद भी कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करेगी। सदन के मुखिया के मुताबिक कांग्रेस किसी दमदार नेता को जिम्मेदारी देने की प्लानिंग में है।

मूणत की जीत के लिए ले रखा था प्रण...हर्षवर्धन ने अब जाकर दाढ़ी बनवाई व केश कटवाया

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। बीते 5 साल से अपने नेता की जीत का सपना संजोए कई पार्टी वर्कर्स 3 दिसम्बर को आये परिणाम के बाद खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। कुछ ने शर्त जीती है,तो कुछ ने जीत को लेकर मन्नत रखी थी। रायपुर के कोटा इलाके के हर्षवर्धन शुक्ला ने रायपुर पश्चिम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेश मूणत की जीत को लेकर संकल्प लिया था कि जब तक राजेश मूणत चुनाव नहीं जीत जाते, वह बाल और दाढ़ी नहीं बनाएंगे। हर्षवर्धन शुक्ला की इच्छा पूरी हो गई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा को बम्पर जीत के साथ ही सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल चुका है। हर्षवर्धन शुक्ला की खुशी तब दोगुनी हो गई,जब राजेश मूणत खुद हर्षवर्धन शुक्ला के घर हज्जाम को लेकर पहुंच गए। मूणत ने उनसे आग्रह किया कि अब अपने बाल कटवा लीजिये। अपने नेता को अपने घर देखकर शुक्ला बहुत खुश हुए और अपनी हजामत करवाई।

अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली में शामिल होने के लिए जिले के युवाओं को मिलेगी नि:शुल्क बस सुविधा

रायपुर. जांजगीर में 15 से 23 दिसम्बर तक आयोजित अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली में भाग लेने वाले जिले के अभ्यर्थियों जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे के निर्देश पर रायपुर जिले के पात्र युवाओं के लिए नि:शुल्क बस सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली के लिए अप्रैल 2023 में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीसीई) का आयोजन किया गया था। जिसमें उत्तीर्ण युवाओं की शारीरिक दक्षता एवं चयन परीक्षा का आयोजन जांजगीर चांपा में 15 से 23 दिसम्बर तक पुलिस लाईन खोखराभाठा जांजगीर में निर्धारित है।

इस दौरान 18 दिसम्बर की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पात्र युवाओं के लिए 17 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे एवं 20 दिसम्बर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले युवाओं के लिए 19 दिसम्बर 2023 को दोपहर 12 बजे जिला रोजगार कार्यालय रायपुर, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर से नि:शुल्क बस सुविधा उपलब्ध होगी। जो वहां से पुलिस लाईन खोखराभाठा जांजगीर के लिए रवाना होगी।

जिला रोजगार कार्यालय के उपसंचालक ने बताया कि नि:शुल्क बस सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र अभ्यर्थी अपना नामांकन जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में 14 दिसम्बर 2023 तक करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9406346840 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

दो धरम हो सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

रायपुर। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कौन होगा राज्य का नया मुख्यमंत्री इसी पर हो रहा है। मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल में कौन-कौन हो सकते हैं शामिल इसके लिए भी सब अपने अनुमान से नाम गिना रहे हैं। इसी क्रम में विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष के लिए भी नाम गिनाये जा रहे हैं। वहीं विधानसभा में सदन के संचालन का जिम्मा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को निभाना होता है,इन दो पदों के लिए भी कई नाम सामने आ रहे हैं। प्रमुखता से दो नाम वरिष्ठता व अनुभव के आधार पर जो कि पहले भी सदन का संचालन कर चुके हैं अध्यक्ष के रूप में धरमलाल कौशिक और उपाध्यक्ष के रूप धरमजीत सिंह का सामने आ रहा है,हालांकि पार्टीगत निर्णय के बाद ही नामों पर मुहर लगेगी लेकिन ज्यादा संभावना यही दिख रही है कि दो धरम कर सकते हैं विधानसभा का संचालन।

बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद

खेतों में कटकर रखे धान हो रहे खराब, किसानों ने नमी वाले धान खरीदने की गुहार लगाई

राजनांदगांव. जिले में बीते सप्ताहभर से हो रहे मौसम में बदलाव के चलते दो दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. ऐसे में इसका असर धान की खड़ी फसलों पर भी देखा जा रहा है. जिले के कई क्षेत्रों में अब तक धान की कटाई नहीं हुई है. वहीं जिन खेतों में कटाई के बाद धान रखा हुआ है उन्हें भी सीधा नुकसान पहुंच रहा है.

मौसम में हो रहे बदलाव के चलते बीते दो दिनों से रुक-रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है. बे-मौसम हो रही इस बारिश से धान की खड़ी फसल बर्बाद हो रही है. खेतों में धान के पौधे झुक गए हैं और बारिश से धान में नमी भी आ रही है. वहीं कुछ खेतों में कटाई के बाद धान रखा हुआ है, इस धन पर भी नमी आ रही है. ऐसे में किसानों को सीधा नुकसान हो रहा है. किसानों का कहना है कि नमी की वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा. किसानों ने मांग की है कि धान खरीदी केन्द्रों में मौसम को देखते हुए नमी वाले धान भी खरीदे जाने चाहिए.

बेमौसम हो रही इस बारिश से धान की फसलों में नमी आ रही है. वहीं खेतों में कटकर रखे धान भी खराब हो रहे हैं. नमी की वजह से किसान धान खरीदी केन्द्रों में अपने धान नहीं बेच पा रहे हैं. जिले के कई किसानों ने अब तक अपने खेतों से धान की कटाई भी नहीं की है. ऐसे में मौसम खराब होने के चलते किसान धान कटाई नहीं कर रहे हैं. अब किसानों ने शासन से मांग की है कि उनके फसलों को हो रहे नुकसान का आकलन कर क्षतिपूर्ति दी जाए.

राजनांदगांव जिले में बड़े पैमाने पर किसानों ने कर्ज लिया है. ऐसे में किसानों को कर्ज माफी की आस भी थी. किसान अगर अपना धान सोसाइटी में ले जाते तो कर्ज की राशि भी काटी जा रही थी. यही कारण रहा कि किसान चुनाव परिणाम आने तक अपनी फसलों को काटना नहीं चाह रहे थे. ऐसे में अब खराब हुई मौसम के चलते किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है.

राज्यपाल ने डॉ. अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें नमन किया। उन्होंने अपने निवास में डॉ. अंबेडकर के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल ने कहा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने समाज के वंचित एवं कमजोर तबके के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सामाजिक समरसता पर बल देते हुए हमेशा शोषितों और पीड़ितों के लिए आवाज बुलंद की और सदैव दलितों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। भारत के संविधान निर्माण में उनकी मुख्य भूमिका थी। वे हमारे देश के गौरव पुत्र है। उनका योगदान चिरस्मरणीय है। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री अमृत कुमार खलखो, उप सचिव श्री दीपक अग्रवाल सहित राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.